राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत-गुजरात,संस्करण बुधवार,09जून-2021 वर्ष-4, अंक -136पृष्ठ-08 मूल्य-01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

राज्यों को आबादी, कोरोना के मामलों के आधार पर मिलेगी वैक्सीन, केंद्र ने जारी की नई वैक्सीनेशन गाइडलाइंस

नई दिल्ली। कोरोना टीकों की खरीद से राज्यों को राहत देने के साथ ही केंद्र सरकार ने अब वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत कोरोना टीकों के आवंटन से लेकर अन्य कई चीजों को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्यों को उनकी आबादी, कोरोना संक्रमण के प्रसार और वैक्सीनेशन की गति के हिसाब से टीके आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि टीकों की बर्बादी यदि होती है तो वैक्सीन के आवंटन में उसका पड़ सकता है। केंद्र की ओर से जारी यह नई गाइडलाइन 21 जून से लागू होने वाली है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि निजी अस्पतालों में लगने वाले कोरोना टीकों के दाम कंपनियों की ओर से तय किए जाएंगे। इसके अलावा राज्यों को छूट दी गई है कि 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों के टीकाकरण के प्रायॉरिटी ग्रुप वे अपने अनुसार तय कर सकते हैं। नई गाइडलाइंस के तहत केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए जाने वाले टीकों की अडवांस में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद राज्यों को जिला प्रशासन को यह जानकारी देनी होगी। यही नहीं किस जिले के लिए कितने टीके आवंटित हुए हैं, इसका ब्योरा भी देना होगा। सरकार ने कहा है कि जिला प्रशासन को टीकों की उपलब्धता के बारे में आम लोगों तक जानकारी पहुंचानी होगी।

निजी अस्पतालों में टीकाकरण की राज्य सरकारें करेंगी निगरानी

केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में टीकों की कीमत को लेकर भी निर्देश दिए हैं। नए आदेश के तहत निजी अस्पतालों में लगने वाले टीकों की कीमत मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की ओर से तय की जाएगी। इसके अलावा किसी भी तरह के बदलाव की स्थिति में अस्पतालों को पहले से जानकारी दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन की एक डोज के लिए निजी अस्पतालों की ओर से टीके की तय कीमत के अलावा 150 रुपये तक ही सर्विस चार्ज की वसूली की जा सकेगी।

बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार सुवेंदु अधिकारी अमित शाह से मिले

पीएम मोदी से भी मिलने की संभावना

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं भाजपा विधायक शुभेन्दु अधिकारी ने मंगलवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद शाह से अधिकारी की यह पहली मुलाकात थी। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। दिल्ली दौरे के दौरान अधिकारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सुवेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल मार्च-अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कड़े मुकाबले में मात दी थी। ममता बनर्जी को हराने के बाद सुवेंदु अधिकारी का सियासी कद काफी हद तक बढ़ा है।

पीएम की बैठक में सुवेंदु अधिकारी के शामिल होने पर ममता बनर्जी ने उठाया था सवाल

गौरतलब है कि मोदी और ममता के बीच

चक्रवाती तूफान 'यास' के कारण हुए नुकसान की समीक्षा को लेकर हुई बैठक में अधिकारी की मौजूदगी से तृणमूल नेता नाराज हो गई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही अधिकारी भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी उक्त बैठक में देर से पहुंची थीं और चक्रवात के नुकसान संबंधी रिपोर्ट देकर वहां से चली गई थीं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि चक्रवात तूफान पर पीएम मोदी की बैठक में विपक्षी नेता के शामिल होने का कोई मतलब नहीं था। बता दें कि भाजपा बंगाल में 3 से 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन गई है।

प्रियंका का केंद्र पर निशाना, बोलीं

कोविड से मौतों को दुष्प्रचार का साधन बना दिया सरकार ने

प्रियंका ने अपने ट्वीट में एक वीडियो शेयर कर सवाल किया, 'कोविड से हुई मौतों के बारे में सरकार के आंकड़ों और श्मशानों-कब्रिस्तानों के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों?

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड-19 महामारी से मौत के आंकड़ों को, घातक कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने का साधन बनाने के बजाय दुष्प्रचार का साधन बना दिया। उन्होंने सरकार से प्रश्न पूछने की अपनी श्रृंखला के तहत वीडियो जारी कर यह दावा भी किया कि महामारी की वजह से मरने वालों के आधिकारिक आंकड़ों तथा विभिन्न शहरों में श्मशानों और कब्रिस्तानों में हुए अंतिम संस्कार की संख्या में बहुत अंतर है।

प्रियंका ने अपने ट्वीट में एक वीडियो शेयर कर सवाल किया, 'कोविड से हुई मौतों के बारे में सरकार के आंकड़ों और श्मशानों-कब्रिस्तानों के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों? उन्होंने यह भी पूछा, 'मोदी सरकार ने आंकड़ों को जागरूकता फैलाने और घातक कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने का साधन बनाने के बजाय दुष्प्रचार का साधन क्यों बना दिया?

सरकार ने बताया

इन लोगों को अब भी 28 दिनों के अंतराल पर मिल सकती है कोविशील्ड की दोनों खुराकें

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जरूरी कार्य से विदेश यात्रा पर जाने वालों को कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक जल्द लगाने को मंजूरी दे दी है। ऐसे लोग अब 28 दिनों के बाद कोविशील्ड की दूसरी खुराक ले सकेंगे। जबकि बाकी लोगों के लिए पूर्व की भांति 12 से 16 सप्ताह की समय सीमा जारी रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रोजगार, शिक्षा, टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जैसे कारणों से जिन लोगों को तुरंत विदेश जाना है लेकिन वे कोविशील्ड की एक खुराक ले चुके हैं तथा दूसरी खुराक लेने में अभी वक्त है। उन्हें यह छूट दी जा रही है। ऐसे लोग जिन्हें पहली खुराक लिए 28 दिन हो गए होंगे, वह इसका फायदा ले सकते हैं। सरकार ने कहा कि ऐसे लोगों को यह सुविधा 31 अगस्त 21 तक के लिए होगी। उनके टीकाकरण प्रमाण पत्र पर पासपोर्ट नंबर भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही उन्हें टीकाकरण के वक्त पासपोर्ट भी पेश करना होगा।

राज्यों को निर्देश-केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वह ऐसे लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी घोषित करें। जो दस्तावेजों की जांच के बाद ऐसे मामलों में

जल्दी टीकाकरण की अनुमति प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे लोगों को अपने दस्तावेजों में टाइप ऑफ वैक्सीन की जगह कोविशील्ड लिखना होगा। अन्य कोई विवरण भरने की जरूरत नहीं है। बता दें कि कोविशील्ड को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वीकृत टीकों की सूची में शामिल किया जा चुका है।

कोरोना के चलते छोटा होगा संसद का मानूसन सत्र?

कोरोना के चलते छोटा होगा संसद का मानूसन सत्र?

नई दिल्ली। कोरोना के चलते सरकार और संसद के अधिकारी जुलाई में संसद के मानसून सत्र की कम समय के लिए आयोजित करने या फिर इसे अगस्त-सितंबर तक स्थगित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। मामले से परिचित अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर ये जानकारी दी है।

बीते तीन संसद सत्रों को कोरोना के ही चलते छोटा करना पड़ा था। वहीं दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। मानसून सत्र आमतौर पर जुलाई में आयोजित किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि 'संविधान के अनुसार, कोई भी सत्र पिछले छह महीने के भीतर शुरू होना चाहिए। इसलिए सरकार के पास मानसून सत्र बुलाने के लिए फिलहाल 24 सितंबर तक का समय है।' भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने

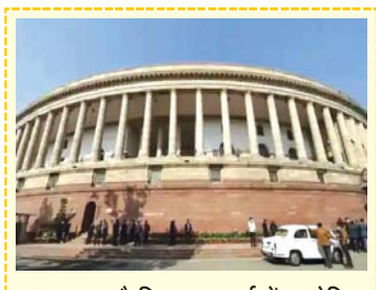

● सुझाव है कि सत्र जुलाई में आयोजित किया जा सकता है ताकि अगर सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आती है, तो संसद कम से कम 15 दिन के लिए चल चुकी होगी। एक अन्य भाजपा नेता ने कहा कि सत्र का समय लंबित विधायी कामकाज और बाहरी सांसदों की सदन में भाग लेने की क्षमता जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करेगा।

बताया कि पार्टी ने अनौपचारिक रूप से छोटा संसद सत्र आयोजित करने की संभावना पर चर्चा की है। ये शायद जुलाई की शुरुआत में होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना मामलों की संख्या अब कम होने लगी है इसलिए हमें कुछ समय इंतजार करना होगा और स्थिति को देखना होगा। सुझाव है कि सत्र जुलाई में आयोजित किया जा सकता है ताकि अगर सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आती है, तो संसद कम से कम 15 दिन के लिए चल चुकी होगी। एक अन्य भाजपा नेता ने कहा कि सत्र का समय लंबित विधायी कामकाज और बाहरी सांसदों की सदन में भाग लेने की क्षमता जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। चूंकि कुछ राज्यों में कोरोना के दैनिक मामले अभी भी अधिक हैं, इसलिए सांसदों को यात्रा करना आसान नहीं होगा।

'डेल्टा' वैरिएंट से महामारी की तीसरी लहर का खतरा

40 फीसद अधिक खतरनाक

नई दिल्ली। देश में महामारी की दूसरी लहर के जिम्मेवार डेल्टा वैरिएंट क्ल1.617.2 का असर अब कमजोर होने लगा है लेकिन दुनिया के अन्य देशों में अभी यह परेशानी का सबब बना हुआ है। इस वैरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'डेल्टा' नाम दिया है। इस वैरिएंट से संक्रमण का पहला मामला पिछले साल अक्टूबर में भारत में ही आया था। कोरोना वायरस के इस डबल म्यूटेंट वैरिएंट 'डेल्टा' ने देश में तबाही मचा दी, और लाखों लोगों को चपेट में ले लिया। बता दें कि डेल्टा वैरिएंट के बाद अब नए वैरिएंट के आने की खबरें हैं। WHO का कहना है कि वायरस के अन्य वैरिएंट अल्फा, बीटा, गामा की तुलना में डेल्टा अधिक खतरनाक है और यह कई गुना तेजी से फैलता है। संगठन ने यह भी कहा जिंदगियों के लिए सबसे अधिक घातक भी यही वैरिएंट है। ब्रिटेन में भी डेल्टा वैरिएंट का खौफ है। यहां महामारी की तीसरी लहर का जिम्मेवार भी इसी वैरिएंट को बताया गया है। यहां के स्वास्थ्य मंत्री मैन हेनकॉक के अनुसार बाकी दोनों वैरिएंट की तुलना में डेल्टा 40 फीसद अधिक खतरनाक है। वहीं सीनियर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में हालिया बढ़ोतरी के पीछे 'डेल्टा' है। इसने 21 जून से निर्धारित अनलॉक योजना को और मुश्किल बना दिया है। उन्होंने बताया कि डेल्टा से संक्रमित अस्पताल में भर्ती अधिकतर लोगों को वैक्सीन की डोज नहीं मिली थी।

सबको मुफ्त टीका, दीवाली तक राशन के लिए भारत सरकार को खर्च करने होंगे 80 हजार करोड़ रुपये

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ऐलान किया कि 21 जून से देश में हर नागरिक के टीकाकरण का खर्चा केंद्र सरकार के जिम्मे होगा। इसके अलावा महामारी से प्रभावित हुए लाखों-करोड़ों लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। हालांकि, इन दोनों ही काम के लिए भारत सरकार को भारी-भरकम खर्चा उठाना पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक, मुफ्त वैक्सीन और राशन मुहैया कराने के लिए भारत को करीब 800 अरब रुपये यानी 80 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी। मामले के जानकार सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार

देश के गरीबों को नवंबर तक मुफ्त राशन देने के लिए अतिरिक्त 700 अरब रुपये आवंटित करेगी। इसके अलावा सरकार को मुफ्त टीकाकरण के लिए भी अतिरिक्त 100 अरब रुपये की जरूरत पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को केंद्र की पिछली टीकाकरण नीति में बदलाव करते हुए ऐलान किया कि अब 18 साल से ज्यादा आयु वाले सभी नागरिकों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार सिर्फ 45 साल से ज्यादा आयु के लाभार्थियों के लिए टीका मुहैया कराती थी और 18 से 44 साल के लोगों के लिए राज्य सरकारें टीका खरीद रही थीं। हालांकि, केंद्र की इस नीति की कई राज्यों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी आलोचना की थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार को 991.2 अरब रुपये का लाभांश आरबीआई से मिला और इसके अलावा संपत्तियों की बिक्री से भी आमदनी की उम्मीद है। अतिरिक्त खर्च को जोड़ लें तो भारत सरकार मुफ्त राशन मुहैया कराने में करीब 1 लाख 13 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। केंद्र सरकार पहले ही वार्षिक बजट में टीकाकरण के लिए 35 हजार करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है। देश में 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में अब तक 23.2 करोड़ लोगों को टीका दिया गया है। इनमें से 3.4 फीसदी लोगों को टीके की दोनों खुराकें लग चुकी हैं। मौजूदा गति से भारत को अपनी 75 फीसदी आबादी को टीका देने में अभी 22 महीने और लगेंगे।

दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा उम्र वाली पूरी आबादी को कैसे लगेगा कोरोना टीका, सरकार ने बताया पूरा प्लान

नई दिल्ली। दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा उम्र वाली पूरी आबादी को कैसे लगेगा कोरोना टीका, सरकार ने बताया पूरा प्लान

केंद्र सरकार ने टीकाकरण नीति में बदलाव के साथ ही दिसंबर तक 18 साल से अधिक आबादी के सभी 94 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना तैयार कर ली है। सरकार ने कहा कि जुलाई तक टीके की 53.6 करोड़ खुराक उपलब्ध हैं, जबकि अगस्त से दिसंबर के बीच 133.6 करोड़ खुराक का इंतजाम किया जा रहा है। इससे सभी 94 करोड़ लोगों को टीका लगा पाना संभव हो सकेगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार टीकाकरण शुरू होने से लेकर जुलाई तक टीकों की उपलब्धता 53.6 करोड़ है। इसमें राज्यों एवं निजी अस्पतालों द्वारा सीधे तौर पर खरीदी गई 18 करोड़ डोज भी शामिल है। अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड की 50 करोड़, कोवैक्सीन की 38.6 करोड़, बायोलॉजिकल ई की 30 करोड़,, जायडस कैडिला की 5 करोड़ तथा स्पूतनिक के 10 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। इन पांच महीनों में 133.6 करोड़ खुराक होगी। इस प्रकार जनवरी से दिसंबर तक कुल 187.2 करोड़ खुराक होंगी। जो 94 करोड़ वयस्क व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होंगी। भूषण के अनुसार यदि फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन आदि से इस बीच टीके मिल जाते हैं, साथ ही घरेलू कंपनी जिनोवा का टीका तैयार हो जाता है या भारत बायोटैक की नेजल वैक्सीन तैयार हो जाती है, तो इससे टीकों की अतिरिक्त उपलब्धता होगी।

टीकाकरण में अब तेजी-मई की शुरुआत में

टीकाकरण में सुस्ती आ रही थी, लेकिन अब इसने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 31 मई को 28 लाख टीके लगे थे, तो 4 जून को 36.5 लाख टीके लगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसमें तेजी आएगी क्योंकि जून में 12 करोड़ डोज उपलब्ध हैं। जबकि मई में यह आठ करोड़ के करीब थीं।

राज्यों को आपूर्ति-भूषण के अनुसार नई टीका नीति लागू होने के बावजूद जिन राज्यों ने टीकों के आर्डर घरेलू कंपनियों को दिए हैं, उनकी आपूर्ति कंपनियों द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें किसी राज्य ने विदेशी कंपनी से अब तक खरीद की हो।

वैक्सीन आवंटन फार्मूला-उन्होंने कहा कि राज्यों को टीके के आवंटन का फार्मूला पूर्व की भांति रहेगा जिसमें टीकाकरण योग्य आबादी को आधार बनाया जाता है।

स्पूतनिक का देश में उत्पादन शुरू-उन्होंने कहा कि रूसी टीके स्पूतनिक का निर्माण देश में सात कंपनियां करने जा रही हैं। इनमें से दो कंपनियों ने कार्य शुरू कर दिया है। इसलिए स्पूतनिक की विदेशों से खरीद की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब यह देश में ही बनेगी तो इसकी कीमतें काफी कम हो जाएंगी।

प्राथमिकता तय कर सकते हैं राज्य-मंत्रालय के अनुसार राज्यों को कुछ हद तक टीकाकरण के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करने का अधिकार होगा। वह अपने प्राथमिकता समूह तय कर सकेंगे। जल्द जारी होने वाले दिशा-निर्देशों में इस बारे में स्पष्टता आ सकती है।

10 राज्यों ने किया अनुरोध-सरकार ने कहा कि मई में पंजाब, केरल, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को पत्र लिखकर टीके की केंद्रीय स्तर पर खरीद की मांग की थी। अन्य राज्यों में सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा त्रिपुरा शामिल हैं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

सबको मुफ्त टीका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल देश के सबसे प्रभावी वक्ता और कम्युनिकेटर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल अनेक उद्देश्यों के लिए करते हैं, इसलिए जब भी वह देश को सीधे संबोधित करते हैं, तब सबको यह उत्सुकता और कुछ व्यग्रता भी होती है कि आखिर इस बार प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं? वैसे भी, वह संभवत- देश को सबसे ज्यादा बार सीधे संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनका कल का संबोधन मुख्यत- दो नीतिगत घोषणाओं के लिए था, और इस मौके का एक और इस्तेमाल उन्होंने कोरोना से लड़ने की सरकार की रणनीति व टीकाकरण अभियान के क्रियान्वयन की आलोचना का जवाब देने के लिए किया। सरकार की कोरोना नियंत्रण और वैक्सीन नीति की कई वजहों से, खासकर दूसरी लहर के मद्देनजर आलोचना होती रही है और एक महत्वपूर्ण मामले में अब सरकार ने सही निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि अब वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत वैक्सीन वह खुद ही खरीदेगी, यानी राज्यों के हिस्से की वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी भी अब केंद्र सरकार की होगी। सिर्फ निजी अस्पताल ही अपना 25 प्रतिशत कोटा वैक्सीन निर्माताओं से सीधे खरीदेंगे और हर टीके पर डेढ़ सौ रुपये का सेवा-शुल्क ले सकते हैं। जब केंद्र सरकार ने पहले अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी घोषित की थी, जिसमें राज्यों को 25 प्रतिशत वैक्सीन सीधे खरीदनी थी, तभी यह बात सामने आई थी कि इससे राज्यों की मुसीबत बढ़ जाएगी। एक तो राज्यों को केंद्र के मुकाबले दोगुनी कीमत चुकानी थी और दूसरे, अलग-अलग राज्य को कितनी वैक्सीन मिल पाएगी, इसे लेकर भी अनिश्चय था। राज्यों पर 45 साल से कम उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाने की जिम्मेदार उठानी थी और दूसरी लहर के मद्देनजर लोगों में वैक्सीन लगाने की जो जल्दबाजी थी, उस वजह से कई राज्यों में वैक्सीन की कमी होने लगी। ऐसे में, कई राज्यों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार से सीधे वैक्सीन खरीदने की कोशिश भी की, पर वे इसलिए नाकाम रहे कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां राज्यों से सीधे लेन-देन करने को तैयार न थीं। तभी से कई जानकार और राज्य सरकारें भी कहती आ रही थीं कि वैक्सीन खरीदने का काम केंद्र सरकार को ही करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की टीकाकरण-नीति पर सवाल खड़े किए थे। अब सरकार ने यह फैसला करके अच्छा कदम उठाया है। इसके बाद दो बातें महत्वपूर्ण हैं- पहली, वैक्सीन वितरण की एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण व्यवस्था तैयार करना और वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने का युद्ध-स्तर पर प्रयास। प्रधानमंत्री के संबोधन में दूसरी बड़ी घोषणा गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने की योजना को नवंबर तक बढ़ाना है। यह भी अच्छा कदम है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अभी गरीबों के लिए रोजी-रोटी का ठीक-ठाक इंतजाम होने में वक्त लग जाएगा। अगर दो वक्त की रोटी का इंतजाम निश्चित हो, तो अन्य समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को गरीबों को सीधे नकदी देने की योजनाओं पर भी जल्दी से विचार करना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के उतार के साथ अब आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं, अगर लोगों के हाथों में पैसा होगा, तो निस्संदेह आर्थिक गतिविधियों को तेजी मिलेगी।

'आज के ट्वीट

मुफ्त

21 जून से 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा।

– पीएम नरेंद्र मोदी

निजी स्कूलों को मिले निजता का अधिकार

न्यायमूर्ति एस.एस. सोढी (अ.प्रा.)

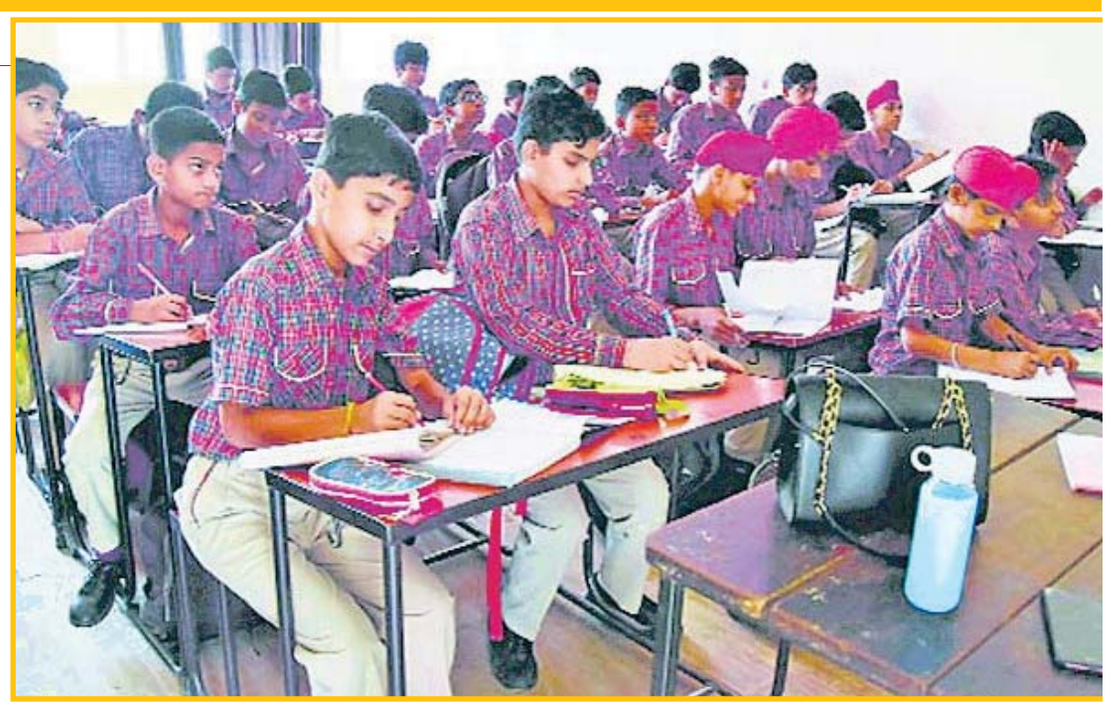

क्या चंडीगढ़ के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को अपनी निजता बनाए रखने का हक है या नहीं? यह विषय इस केंद्रशासित प्रदेश द्वारा दिए एक आदेश के संदर्भ में उठ रहा है, जिसमें प्रशासन ने निजी स्कूलों को अपना वित्तीय विवरण (फाइनेंशियल स्टेटमेंट) वेबसाइट पर डालने को कहा है, ताकि छात्र और अभिभावक देख सकें, दूसरे शब्दों में, यह सार्वजनिक हो। यह सब उसके बावजूद है जब स्कूल प्रबंधन हर साल संबंधित विभागों को आय-व्यय और बजट संबंधी लेखा-जोखा मुहैया करवाता है। इस डर के साथ कि वित्तीय लेखा-जोखा वेबसाइट पर अपलोड करने पर कहीं निजी शिक्षण संस्थान को बेवजह नुक्ताचीनी का सामना न करना पड़े और संभवतः अभिभावक और दीगर तत्व बेजा अड़ंगा न डालने लगें, जिससे कि विद्यालय के सुचारु प्रबंधन में अड़चनें पैदा हो जाएं, निजी स्कूल उक्त मामले को उच्च न्यायालय ले गए। खंडपीठ ने केस नं. सीडब्ल्यू 7706 (2020), जो इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन, चंडीगढ़ बनाम भारत सरकार के बीच चला, उसमें 28 मई को दिए फैसले में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों को अपनी वित्तीय जानकारी वेबसाइट पर डालने संबंधी दिए आदेश को सही ठहराया है। इसमें कहा गया 'अभिवावकों से स्कूलों द्वारा बेजा मुनाफा कमाने वाली शिकायतों के बाद प्रशासन को आय-व्यय का ब्योरा अपलोड करने का आदेश देना पड़ा था।' इसमें आगे यह कहा 'न तो राज्य सरकारें और न ही संबंधित विभाग के अफसर स्कूलों की व्यावसायिक चार्टर्ड अकांउटेंट्स द्वारा बनाई लेखा रिपोर्टों पर गहराई से विचार करते हैं, अतः यदि निजी शिक्षण संस्थान अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी उपलब्ध करवाएंगे तो इससे पारदर्शिता बनेगी और यह इस ध्येय की पूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक होगी कि कोई संस्थान बेजा मुनाफाखोरी और दाखिला फीसें इत्यादि नहीं वसूल रहा। इसमें कोई शक नहीं कि अनेक निजी स्कूल हर साल दाखिला फीस लेने और अनावश्यक मुनाफा बनाने में लिप्त हैं। चूंकि संस्थानों द्वारा पेश किए वित्तीय विवरण व्यावसायिक माहिरों द्वारा बनाए गए होते हैं, इसलिए संबंधित सरकारी अधिकारी से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह इनमें चतुराई से छिपाए सत्य को खोज निकालें।' आगे यह आदेश कहता है 'यदि संस्थानों का वित्तीय विवरण वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तो छात्रों के अभिभावक भी इनको देख पाएंगे। संभवतः कई ऐसे माता-पिता जरूर होंगे, जिनकी अकाउंटिंग के क्षेत्र में महारत हो, और वे पड़ताल कर प्रशासन की यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि कोई शिक्षा संस्थान या स्कूल बेजा मुनाफा अथवा दाखिला फीसें न लेने पाए।' गौरतलब है कि आखिर न्यायालय ने यह कैसे मान लिया कि निजी स्कूलों के व्यावसायिक माहिरों द्वारा बनाए वित्तीय विवरणों की गहराई से पड़ताल कर वास्तविकता खोज पाने में सरकारी विभाग के अधिकारी सक्षम नहीं हैं। आदर सहित कहना चाहूंगा कि यह तर्क सराहना योग्य नहीं कहा जा सकता। यह पहले से कैसे माना जा सकता है कि वे इतने काबिल नहीं हैं। अवश्य ही विभाग ऐसे विवरण केवल अपने दफ्तरों को भरने के लिए नहीं मांगते। यदि कोई स्कूल ज्यादा दाखिला फीस या अन्य अनाधिकारिक पैसा मांग रहा होगा तो संबंधित विभाग से उम्मीद है वे इतने काबिल तो हैं ही कि छिपे पेच को पकड़ पाएं और यथेष्ट कार्रवाई करें। लगता है वेबसाइट पर वित्तीय विवरण डलवाने को अदालत ने प्रभावित किया है, वह यह है कि शायद कुछेक स्कूल पहले ऐसा कर चुके हैं। यदि कुछ कर सकते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि बाकी सब भी यही करें, जब तक कि उन पर ऐसा करने की कानूनी बाध्यता न हो। जब निजी स्कूलों द्वारा निजता का विषय उठाया गया तो अदालत का कहना था 'यह आदेश किसी भी तरह उनकी निजता का हनन नहीं है, वैसे भी शिक्षा देने का काम परमार्थ करने वाला व्यवसाय है।' जैसा कि सर्वविदित है, सब निजी स्कूल परमार्थ संस्थान नहीं हैं, न ही उन्हें होने की जरूरत है। तथ्य तो यह है कि बतौर एक मुनाफादायक व्यवसाय निजी स्कूल बनाने पर कोई रोक नहीं है। किसी को भी हैरानी होगी जब यह कहा जा रहा है कि निजी स्कूलों का वित्तीय विवरण वेबसाइट पर डालने पर उनकी निजता का हनन नहीं होगा। अदालत के इस निर्णय की आगे न्यायिक पड़ताल हो सकती है। अब जो भी है, आखिरी आदेश सर्वोच्च न्यायालय से आना है। निजी स्कूलों की बात करें तो देश में बड़ी आबादी को शिक्षित करने में इनकी भूमिका निश्चित तौर पर कम नहीं है और कभी माननी भी नहीं चाहिए। लोकहितकारी व्यवस्था को अपनाने वाले हमारे जैसे मुल्क में वैसे तो यह सरकार का दायित्व है कि सबको शिक्षा मुहैया करवाए। चूंकि सरकारें ऐसा करने में असफल रही हैं, इसलिए निजी स्कूल वह भरपाई करते हैं जो वास्तव में सरकार का फर्ज है। यह विरोधाभासी है कि सरकारे निजी स्कूलों द्वारा वसूले जा रहे पैसे पर तो बहुत चिंतित दिखाई पड़ती हैं लेकिन सरकारी स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर कभी कुछ कहा हो, यह शायद ही सुनने को मिला है। बच्चे को निजी स्कूल में भर्ती करवाते वक्त हर अभिभावक को फीस और अन्य खर्चों के बारे मे भली भांति पता होता है, यह सब जानने के बाद ही अधिकांश माता-पिता औलाद को वहां पढ़ाना चुनते हैं। बच्चे को ऐसे स्कूल में भर्ती करवाने के बाद फिर फीस को लेकर शिकायत करने का क्या औचित्य है? स्कूल चाहे सरकारी हो या निजी, देश को बहुत बड़ी संख्या में और अधिक विद्यालयों की जरूरत है, खासकर वह जो गुणवत्ता वाली शिक्षा दे सकें। एक अच्छा निजी स्कूल बनाने में बहुत धन और प्रयास लगते हैं। लेकिन जैसा सरकारों का निजी स्कूलों के प्रति मौजूदा रवैया है, ऐसे में कोई नया स्कूल खोलना क्यों पसंद करेगा? यहां सर्वोच्च न्यायालय की 11 सदस्यीय खंडपीठ द्वारा टीएमएपी बनाम कर्नाटक सरकार मुकदमे में दिए फैसले का उल्लेख करना जरूरी है, जिसमे कहा गया था 'यह आम जनता के हित में है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले और अधिक स्कूल खोले जाएं, स्कूल प्रबंधन को नियुक्तियां करने, छात्रों की भर्ती और वसूली जाने वाली फीस में खुदमुख्तारी और अबाधित जिम्मेवारी मिलने से यह सुनिश्चित हो पाएगा कि इस तरह के संस्थान स्थापित हो पाएं।' सरकारें शिक्षा संस्थानों पर अनावश्यक आदेश लादकर देश में शिक्षा के हितों से खिलवाड़ न करें, वरना यह 'पेड़ गंवाने की एवज में वन' से हाथ धोने जैसा होगा। लेखक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं।

ज्ञान गंगा

खेती

सद्गुरु/ हमारे देश ने बहुत सी उल्लेखनीय वैज्ञानिक सफलतायें हासिल की हैं और साथ ही कई बड़े उद्यम लगाने में भी हम सफल रहे हैं जो हम सब के लिए गर्व का विषय है। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा है। उद्योग व्यापार में बहुत से बड़े उद्यम हमने देश में स्थापित किये हैं लेकिन इस सब के बीच हमारी सबसे महान उपलब्धि ये है कि बिना किसी विशेष तकनीक और बुनियादी ढांचे के, हमारे किसान आज भी 130 करोड़ लोगों को बस अपने पारंपरिक ज्ञान के सहारे खाना खिला रहे हैं। दुर्भाग्यवश हमें हमारा भोजन प्राप्त कराने वाले किसान के बच्चे भूखे हैं और वो खुद अपनी जान ले लेना चाहता है। पिछले 10 वर्षों में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इतने लोग तो उन चार युद्धों में भी नहीं मरे जो भारत ने लड़े हैं। यह सोच कर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। हमारे देश को प्रकृति का ऐसा वरदान प्राप्त है कि वो सारी दुनिया का अन्नदाता बन सकता है क्योंकि हमारे देश में लैटीट्यूड से जुड़ा या अक्षांश-संबंधी फैलाव मौजूद है, जिसमें ऋतुओं की विविधता, अच्छी मिट्टी, जलवायु की उचित स्थिति शामिल है। सबसे बढ़कर, हमें ऐसे लोगों की विशाल संख्या प्राप्त है जो मिट्टी को भोजन में बदलने का जादू जानते हैं। हम अकेले देश हैं, जिसे ऐसे वरदान प्राप्त हैं, लेकिन अगर हम इस व्यावसायिक क्षेत्र को बहुत बड़ी आमदनी देने वाला क्षेत्र नहीं बनाते हैं, तो अगली पीढ़ी के कृषि को अपनाने की उम्मीदें बहुत कम हैं। सिर्फ इसी से आबादी ग्रामीण भारत में रु की रहेगी। अगर खेती से होने वाली आमदनी को हम कुछ गुना नहीं बढ़ाते, तो ग्रामीण भारत का आधुनिकरण एक सपना ही रह जाएगा, लेकिन कृषि को बड़े रूप में फायदा देने वाले एक उद्यम की तरह बनाने में हम सफल नहीं हो रहे क्योंकि सबसे बड़ी बाधा उनकी जमीनों का बहुत छोटा होना है-लोगों की जमीनें बहुत छोटी हैं। हजारों सालों से इन जमीनों पर खेती हो रही है। भारत के किसानों के पास औसतन प्रति किसान बस 1 हेक्टेयर से कुछ ही ज्यादा जमीन है। तो इतनी छोटी जमीन में किसान जो भी धन लगाता है वो डूब ही जाता है। हमारे किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले दो मुख्य कारण, जो उन्हें गरीबी और मौत की ओर धकेल रहे हैं-वे हैं सिंचाई साधनों में होने वाला बड़ा खर्च।

संकट में मदद को आगे आये सरकार

भरत झुनझुनवाला

वैश्विक सलाहकार कम्पनी मैकेंजी ने अक्तूबर 2020 के एक अध्ययन में कहा था कि यूरोप के छोटे उद्योगों का स्वयं का अनुमान है कि आधे उद्योग आने वाले 12 माह में बंद हो जायेंगे। भारत की परिस्थिति ज्यादा दुष्कर है क्योंकि हमारे छोटे उद्योगों ने लॉकडाउन के साथ-साथ नोटबंदी और जीएसटी की मार भी खाई है। ई-कॉमर्स और बड़ी कंपनियों ने छोटे उद्योगों के बाजार पर कब्जा कर लिया है। विषय यह है कि छोटे उद्योग यद्यपि माल महंगा बनाते हैं परन्तु वे हमारे भविष्य के उद्यमियों के इनक्यूबेटर अथवा लेबोरेटरी भी हैं। आज का छोटा उद्यमी कल बड़ा हो सकता है। धीरुभाई अम्बानी किसी समय छोटे उद्यमी थे। यदि उनके छोटे उद्योग को पनपने का अवसर नहीं मिलता तो वे कभी बड़े भी नहीं होते। साथ ही ये भारी संख्या में रोजगार सृजित करते हैं। रोजगार उत्पन्न होने से जनता की सृजनात्मक क्षमता उत्पादक कार्यों में समाहित हो जाती है। यदि हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो वे अंततः आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होंगे जो हो भी रहा है। औरंगाबाद, महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की माने तो उनके एमए पढ़े छात्र भी अब एटीएम तोड़ने जैसे कार्यों में लिप्त हो गये हैं, चूंकि वे बेरोजगार हैं। बड़ी संख्या में लोगों के अपराध में लिप्त होने से सुरक्षा का खर्च बढ़ता है, देश पर पुलिस का खर्च बढ़ता है, नागरिकों में असुरक्षा की भावना विकसित होती है और सामाजिक और पारिवारिक ढांचा विघटित होता है। देश में असुरक्षित वातावरण के कारण विदेशी कम्पनियां भी निवेश करने से कतराती हैं। इसलिए यदि हम छोटे उद्योगों से बने माल के ऊंचे दाम को सहन करें तो इस भार के बावजूद आर्थिक विकास हासिल होता है। सामाजिक वातावरण आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और निवेश के अनुकूल स्थापित हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम बड़े उद्योगों से उत्पादन कराएं तो बेरोजगारी और अपराध दोनों बढ़ते हैं। यद्यपि बाजार में सस्ता माल उपलब्ध होता है परन्तु अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है क्योंकि अपराध बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारों को न्यूनतम सुरक्षा देने को मनरेगा जैसे कार्यक्रमों पर सरकार को खर्च भी अधिक करना पड़ता है। मनरेगा पर खर्च की गयी रकम मूल रूप से अनुत्पादक कार्यों में लगती है। वही रकम यदि छोटे उद्योगों को लगाने में लगायी जाये तो उत्पादन बढ़ेगा। अतएव केवल बड़े उद्योगों के सहारे आर्थिक विकास की नीति विफल होने की संभावना ज्यादा है। पिछले 6 वर्षों में हमारी आर्थिक विकास दर गिरने का यह एक बड़ा कारण दिखता है। छोटे उद्योगों को जीवित रखने के लिए कोशिश हो कि उनकी उत्पादन लागत कम आये। इसके लिए ऋण देने के अतिरिक्त ठोस कदम उठाने होंगे। यूरोपीय यूनियन की छोटे उद्योगों की गाइड बुक में सुझाव दिया गया है कि छोटे उद्योगों को ट्रेनिंग, रिसर्च एवं सूचना उपलब्ध करने के लिए उनके गुट अथवा क्लस्टर बनाने चाहिए और इन क्लस्टरों का संचालन छोटे उद्योगों के अपने संगठनों के हाथ में दे देना चाहिए। जैसे वाराणसी में यदि बुनकरों को समर्थन देना है तो वाराणसी के बुनकरों के संगठन के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग, रिसर्च और सूचना उपलब्ध कराई जाए। उनके संगठन को सही ज्ञान होता है कि किस प्रकार की तकनीक की जरूरत है और किस प्रकार की ट्रेनिंग कामयाब होगी। यदि यही कार्य किसी एनजीओ अथवा किसी सरकारी तंत्र के माध्यम से कराया जाता है तो उन्हें जमीनी स्थिति का ज्ञान नहीं होता। तमाम एनजीओ ऐसी योजनाओं में अपनी रोटी सेंक रहे हैं। इस दिशा में भारत सरकार की नीति विपरीत दिशा में दिख रही है। छोटे उद्योगों के परिसंघ के सचिव अनिल भारद्वाज के अनुसार सरकार द्वारा छोटे उद्योगों की समस्याओं के निवारण के लिए जो बोर्ड बनाये गये हैं, उसमें पूर्व में छोटे उद्योगों के संगठनों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त स्थान दिया जाता था। बीते दिनों में सरकार ने इन बोर्डों में केवल अधिकारी और नेताओं की नियुक्ति की है और छोटे उद्योगों के संगठनों की सदस्यता पूर्णतया समाप्त कर दी है। सरकार को छोटे उद्योगों को इस कठिन समय में वित्तीय सहायता देने पर विचार करना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अप्रैल, 2020 के एक अध्ययन में बताया गया है कि ब्राजील, कनाडा और न्यूजीलैंड में छोटे उद्योगों द्वारा अपने श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन का एक अंश कुछ समय के लिए सब्सिडी के रूप में दिया गया है, जिससे कि छोटे उद्योग भी जीवित रहें और और उनमें कार्यरत श्रमिक भी अपना जीवन निर्वाह कर सकें। सरकार ने छोटे उद्योगों को सरल ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया है जो कि सामान्य परिस्थितियों में सही बैठता है। लेकिन जिस समय छोटे उद्योगों द्वारा बनाया गया माल बाजार में बिक ही नहीं रहा है, उस समय उनके द्वारा ऋण लेकर कठिन समय पार करने के बाद उनके ऊपर ऋण का अतिरिक्त बोझ आ पड़ेगा और वे ऋण के बोझ से उबर ही नहीं पायेंगे। इसलिए ऋण पर सब्सिडी देने के स्थान पर उसी रकम को सीधे नगद सब्सिडी के रूप में देना चाहिए। छोटे उद्योगों द्वारा अक्सर आयातित कच्चे माल का उपयोग करके माल तैयार किया जाता है और फिर उसको बाजार में बेचा जाता है अथवा निर्यात किया जाता है। इनमें से एक कच्चा माल प्लास्टिक है। सरकार ने प्लास्टिक पर आयात कर बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण कच्ची प्लास्टिक का दाम अपने देश में बढ़ गया है और विशेषज्ञों के अनुसार प्लास्टिक का माल बनाने वाले छोटे उद्योग बंद प्राय हो गए हैं। यह परिस्थिति अन्य कच्चे माल की हो सकती है। ऐसे कच्चे माल पर आयात कर घटना चाहिए। सरकार को अपनी नीतियों का पुनरावलोकन करके छोटे उद्योगों को राहत पहुंचाना चाहिए।

आज का राशिफल

मेष बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें।

वृषभ सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। वाणी की सौम्यता आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। धन लाभ के योग हैं।

मिथुन जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। किसी मित्र या रिश्तेदार से धन लाभ के योग हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। विरोधी परास्त होंगे।

कर्क संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

सिंह पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। शासन सत्ता से तनाव मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

कन्या आर्थिक योजना फलीभूत होगी। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। भारी व्यय की संभावना है। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे।

तुला जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। विरोधी परास्त होंगे।

वृश्चिक बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। वाद-विवाद की स्थिति आपके लिए हितकर नहीं होगी।

धनु व्यावसायिक योजना सफल होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। वाद विवाद की स्थिति आपके लिए हितकर नहीं होगी।

मकर पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। अनावश्यक व्यय हो सकता है।

कुम्भ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आमोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी।

मीन रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जनों से पीड़ा मिलेगी। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे।

इनकम टैक्स की नई वेबसाइट में आई तकनीकी खामियां, वित्त मंत्री ने उठाया यह कदम

बिजनेस डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इन्फोसिस और उसके चेयरमैन नंदन निलेकणि से आयकर विभाग की नई ई-फाइलिंग वेबसाइट में आ रही तकनीकी खामियों को दूर करने को कहा। ट्विटर पर भारी संख्या में उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के बाद वित्त मंत्री ने यह कदम उठाया। इन्फोसिस को 2019 में अगली पीढ़ी की आयकर फाइलिंग प्रणाली तैयार करने का अनुबंध दिया गया था। इसका मकसद रिटर्न की प्रसंस्करण प्रक्रिया में लगने वाले 63 दिन के समय को कम कर एक दिन करने और रिफंड प्रकिया को तेज करना है। पोर्टल सोमवार शाम चालू हो गया। वित्त मंत्री ने मंगलवार सुबह ट्विटर के जरिए नए पोर्टल **www.incometa&.gov.in** शुरू होने की घोषणा करते हुए कहा, अनुपालन अनुभव को करदाताओं के और अनुकूल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। पोर्टल सोमवार रात 8.45 बजे परिचालन में आ गया लेकिन कुछ ही समय बाद उनके ट्विटर टाइमलाइन पर उपयोगकर्ताओं की कई शिकायतें आ गईं। बाद में सीतारमण ने ट्विटर पर लिखा, मैंने अपने टाइमलाइन पर तकनीकी खामियों के बारे में शिकायतें देखी हैं। उम्मीद है कि इन्फोसिस और नंदन निलेकणि प्रदान की जा रही सेवा की गुणवत्ता में हमारे करदाताओं को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने एक उपयोगकर्ता के ट्वीट का हवाला देते हुए, करदाताओं के लिए अनुपालन में सुगमता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उपयोगकर्ता ने अपने ट्वीट में नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन में दिक्कत होने की शिकायत की थी। उल्लेखनीय है कि इन्फोसिस ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल भी तैयार किया था। इसका उपयोग जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग में किया जाता है। प्रमुख आईटी कंपनी को जीएसटीएन पोर्टल को लेकर भी करदाताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा था।

जून के पहले सप्ताह में बिजली की खपत 12.6 प्रतिशत बढ़ी

नयी दिल्ली, देश में बिजली की खपत जून के पहले सप्ताह में 12.6 प्रतिशत बढ़कर 25.38 अरब यूनिट (बीयू) पर पहुंच गई। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली की मांग में सुधार की रफ्तार अभी सुस्त बनी हुई है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल जून के पहले सप्ताह में बिजली की खपत 22.53 अरब यूनिट रही थी। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले साल के निचले आधार प्रभाव की वजह से बिजली की खपत और मांग में सुधार की रफ्तार सुस्त रही है। पिछले साल पूरे जून महीने में बिजली की खपत करीब 11 प्रतिशत घटकर 105.08 अरब यूनिट रही थी। जून, 2019 में यह 117.98 अरब यूनिट थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की वजह से कई राज्यों में लॉकडाउन और अंकुशों के बावजूद इस साल मई के पहले सप्ताह में बिजली की खपत 26.24 अरब यूनिट रही थी। इस लिहाज से मई के पहले सप्ताह की तुलना में जून के पहले सप्ताह में बिजली की खपत में 3.35 प्रतिशत की गिरावट आई है। जून के पहले सप्ताह में व्यस्त समय की पूरी की गई बिजली की मांग पिछले साल की तुलना में करीब 15 प्रतिशत बढ़कर 168.72 गीगावॉट (सात जून) रही। पिछले साल छह जून को यह 146.53 गीगावॉट रही थी। जून, 2019 में व्यस्त समय की पूरी की गई बिजली की मांग 181.52 गीगावॉट (चार जून) रही थी। पिछले साल पूरे जून माह में व्यस्त समय की बिजली की मांग घटकर 164.98 गीगावॉट रह गई, जो इससे पिछले साल समान महीने में 182.45 गीगावॉट रही थी।

शिखर से फिसला शेयर बाजार

बिजनेस डेस्क:

बैंकिंग एवं वित्तीय कंपनियों में बिकवाली के दबाव में घरेलू शेयर बाजारों में आज गिरावट रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 52.94 अंक यानी 0.10 प्रतिशत लुढ़ककर 52,275.57 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11.55 अंक यानी 0.07 प्रतिशत फिसलकर 15,740.10 अंक पर बंद हुआ। सोमवार को दोनों सूचकांक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर रहे थे। दिग्गज कंपनियों के उलट मझौली और छोटी कंपनियों में निवेशकों ने पैसा लगाया। बीएसई का मिडकैप 0.38 प्रतिशत चढ़कर 22,773.33 अंक पर और स्मॉलकैप 0.93 प्रतिशत की बढ़त में 24,826.64 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। बैंकिंग एवं वित्तीय कंपनियों में बिकवाली से बाजार पर दबाव बना। सेंसेक्स में भारतीय स्टेट बैंक का शेयर 1.21 प्रतिशत, एचडीएफसी का 1.18 प्रतिशत, कोटक महिंद्रा बैंक का 1.11 प्रतिशत और एचडीएफसी बैंक का 1.01 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ। आईटी, टेक, दूरसंचार और स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनियों में लिवाली रही। टेक महिंद्रा का शेयर 2.53 फीसदी, भारती एयरटेल का 1.91 फीसदी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 1.83 फीसदी, इंफोसिस का 1.68 फीसदी, टाइटन का 1.63 फीसदी, डॉ. रेड्डीज लैब का 1.07 फीसदी और आईटीसी का 1.04 फीसदी चढ़ा। एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट रही। चीन का शंघाई कंपोजिट 0.54 प्रतिशत, जापान का निक्केई 0.19 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.13 प्रतिशत और हांगकांग का हैंगसेंग 0.02 प्रतिशत टूट गया। यूरोप में शुरुआती कारोबार में ब्रिटेन का एफटीएसई 0.19 प्रतिशत मजबूत हुआ जबकि जर्मनी के डैक्स में 0.14 प्रतिशत की गिरावट रही।

ग्लोबल इंटरनेट डाउन: दुनियाभर की कई वेबसाइट डाउन, यूके सरकार की भी साइट पड़ी ठप

बिजनेस डेस्क:

दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इंटरनेट ठप होने से हड़कंप मच गया है. खबरों के मुताबिक, न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन समेत बड़ी अंतरराष्ट्रीय न्यूज वेबसाइट और पोर्टल इस कारण डाउन हो गए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक प्राइवेट सीडीएन में समस्या आने के कारण इंटरनेट में तकनीकी खामी सामने आई है। इस बारे में और जानकारी हासिल की जा रही है। खबरों के मुताबिक, तमाम पापुलर वेबसाइट रेडिट, स्पॉटिफाई, पेपल, शॉपिफाई आदि भी ठप हो गई हैं। गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी और फाइनेंशियल टाइम्स जैसी साइटों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा है। माना जा रहा है कि लोकप्रिय सीडीएन प्रोवाइडर फास्टली में दिक्कत के कारण ऐसा हुआ है।

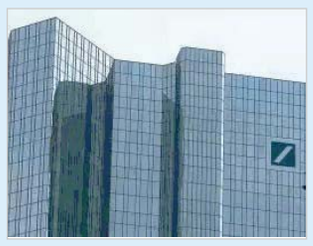

मुद्रास्फीति की उपेक्षा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को टाइम बम पर बिठा देती है: अर्थशास्त्री

नई दिल्ली। ड्यूश बैंक ने सोमवार को एक नोट में कहा कि अगर फेडरल रिजर्व अपरिवर्तित ब्याज दरों के अपने मौजूदा नीतिगत रुख पर कायम रहता है, तो मुद्रास्फीति में वापसी होगी, भले ही कीमतों में वृद्धि अस्थायी होगी। ये रिपोर्ट बिजनेस इनसाइडर ने दी है। मुख्य अर्थशास्त्री और शोध के वैश्विक प्रमुख डेविड फोकट्र्स-लैंडौ के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों ने कहा, हमें उम्मीद है कि मुद्रास्फीति के दबाव फिर से उभरेंगे क्योंकि फेड अपनी धैर्य की नीति के साथ जारी है। 2023 तक एक साल और लग सकता है लेकिन मुद्रास्फीति फिर से उभरेगी। अन्य अर्थशास्त्रियों के विपरीत, जो मानते हैं कि मुद्रास्फीति के दबाव समय के साथ कम हो जाएंगे, ड्यूश बैंक के विश्लेषकों का मानना है कि प्रोत्साहन का प्रवाह वास्तव में निकट अवधि में मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा। अर्थशास्त्रियों ने कहा, मुद्रास्फीति की उपेक्षा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को टाइम बम पर बैठा देती है। मुद्रास्फीति के अतीत के दर्दनाक सबक को केंद्रीय बैंकरों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय बैंकर जितने लंबे समय तक अपने हाथों पर बैठे रहेंगे, इसे संबोधित करना उतना ही मुश्किल होगा। अर्थशास्त्रियों ने कहा प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं, विशेष रूप से समाज में सबसे कमजोर लोगों के लिए। दुर्भाग्य से, जब केंद्रीय बैंक इस स्तर पर कार्य करेंगे, तो उन्हें अचानक नीति परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाएगा, जिससे नीति निर्माताओं के लिए उन सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा ।

शॉपमैटिक ने ऑनलाइन स्टोर के लिए शुल्क में छूट की घोषणा की

नई दिल्ली।

छोटे और मध्यम व्यवसायों और उद्यमियों की मदद के लिए, ई-कॉमर्स एनेबलर शॉपमैटिक ने 3 जून से 31 अगस्त, 2021 के बीच साइन अप करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए शून्य होस्टिंग चार्ज की घोषणा की है। शॉपमैटिक के प्रेरणादायक उद्यमिता कार्यक्रम के रूप में, व्यापारी बिना किसी साइन-अप शुल्क के अपनी ई-कॉमर्स उपस्थिति स्थापित करने के लिए पूरे शॉपमैटिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सक्षम होंगे। जब भी वे बिक्री करेंगे तो उन्हें प्रति लेनदेन 3 प्रतिशत का मामूली शुल्क देना होगा। कंपनी ने कहा कि यह कदम इच्छुक उद्यमियों और छोटे व्यवसाय मालिकों को अपने व्यवसाय को ऑनलाइन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खासकर इन कठिन समय में उठाया जा रहा है। उस समय से 90 दिनों के लिए, वे साइन अप करेंगे और व्यवसाय के मालिक हर सफल लेनदेन पर 3 प्रतिशत का भुगतान करते हुए अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए शॉपमैटिक की तकनीकी-आधारित सुविधाओं की विशाल श्रृंखला तक पहुंच सकेंगे। शॉपमैटिक व्यापारियों को ऑनलाइन जाने के लिए चार अलग-अलग तरीके प्रदान करता है। प्रचार अवधि के दौरान, व्यापारी उपलब्ध चार विकल्पों में से किसी में भी अपनी ऑनलाइन - शॉपमैटिक वेबस्टोर, शॉपमैटिक चैट, शॉपमैटिक सोशल और शॉपमैटिक मार्केटप्लेस में से अपना विकल्प चुन सकते हैं। इस पहल पर बोलते हुए, शॉपमैटिक के सीईओ और सह-संस्थापक, अनुराग अवुला ने कहा, मौजूदा चुनौतीपूर्ण माहौल में ऑनलाइन बिक्री शुरू करने के लिए व्यवसायों का समर्थन करने के हमारे निरंतर व्यवसायों के लिए अगले 90 दिनों के लिए मासिक होस्टिंग शुल्क ऑनलाइन प्राप्त करना हम और भी आसान बना रहे हैं। सीईओ अनुराग अवुला ने कहा, हम अपने बाजारों में एसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों को बिना किसी होस्टिंग शुल्क के प्लेटफॉर्म पर साइन-अप करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और अपनी ऑनलाइन सफलता को चलाने के लिए शॉपमैटिक प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएंगे। प्रेरणादायक उद्यमिता कार्यक्रम के माध्यम से, शॉपमैटिक कंपनी के अनुसार वो निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान महत्वाकांक्षी उद्यमियों के एक बड़े समूह के लिए अपने मंच का विस्तार कर रहा है।

फाइजर ने रखी कानूनी मामले अमरीका में निपटाने की शर्त

बिजनेस डेस्क:

कोरोना वैक्सीन बना रही अमरीका की कंपनी फाइजर ने भारत को वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। फाइजर चाहती है कि वैक्सीन को लेकर पैदा होने वाले किसी भी कानूनी विवाद की सुनवाई अमरीका की अदालत में हो। इसके अलावा कंपनी दवा से होने वाले संभावित नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति के दावों पर संरक्षण चाहती है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कंपनी के साथ वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। हालांकि इस बातचीत के दौरान सरकार दवा से होने वाले संभावित नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति के दावों पर संरक्षण देने को तैयार है लेकिन वह कानूनी मामलों की सुनवाई विदेशी कोर्ट में करवाए जाने की शर्त मानने को तैयार नहीं है।आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि फाइजर ने क्षतिपूर्ति के दावों पर संरक्षण की जो शर्त रखी है वह यदि विदेशी कंपनी को दी जाती है तो घरेलू वैक्सीन निर्माताओं को भी यह राहत दी जाएगी। देश में वैक्सीन की आपूर्ति बनाने को लेकर सरकार कई कदम उठा रही है। जिसमें बिना गारंटी के एडवांस पेमेंट किया जाना भी शामिल है। कानूनी मामलों की सुनवाई अमरीकी अदालत में किए जाने की शर्त को लेकर गतिरोध बना हुआ है। यदि यह मामला संसद में जाता है तो वहां से इस तरह की राहत मिलने की संभावना नहीं है। इसके बावजूद सरकार कंपनी की शर्तों पर काम कर रही है और जल्द ही इस मामले में सकारात्मक नतीजे आने की संभावना है। यदि देश में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बाद किसी को उसका साइड इफैक्ट होता है और इससे किसी को शारीरिक क्षति होती है तो वह सामान्य स्थिति में कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। फाइजर इसी तरह के दावों से संरक्षण चाहती है क्योंकि अभी तक वैक्सीन लगाए जाने के बाद इसके साइड इफैक्ट्स के पूरे परिणाम सामने नहीं आए हैं। फाइजर के साथ चल रही बातचीत की शर्तों के बाद भारत में कोविशील्ड की आपूर्ति कर रही सीरम इस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी क्षतिपूर्ति के दावों पर संरक्षण की मांग की है और यदि फाइजर को यह राहत दी जाती है तो सीरम इंस्टीट्यूट को भी यह राहत मिल सकती है।

कोरोना से बचाव की तैयारी

- वैक्सीन आपूर्ति को लेकर फाइजर से साथ सरकार की बातचीत शुरुआती चरण में
- कंपनी दवा से होने वाले संभावित नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति के दावों पर संरक्षण चाहती है
- फाइजर की शर्तों में मामलों के निपटान को लेकर अदालत का अधिकार क्षेत्र भी एक शर्त है
- सरकार इन विषयों को लेकर फाइजर के साथ बातचीत कर रही है
- वैक्सीन की आपूर्ति जुलाई से शुरू हो सकती है
- स्थानीय वैक्सीन निर्माता भी क्षतिपूर्ति के दावों पर संरक्षण चाहते हैं

कोरोना की मार: मुंबई का Hyatt Regency होटल हुआ बंद, सैलरी देने के नहीं है पैसे

बिजनेस डेस्क: कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में जमकर कहर बरपाया। हालांकि अब इस लहर का असर कम हो रहा है लेकिन इसकी मार हर क्षेत्र पर पड़ी। कोरोना संकट की दूसरी लहर हॉस्पिटैलिटी एवं टूरिज्म सेक्टर पर कहर बनकर टूटी है। कई राज्यों में इसका असर देखने को मिला है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बड़े होटल पर भी कोरोना का साइड इफेक्ट देखने को मिला है।

ये है होटल का बयान

मुंबई के हयात रिजेंसी (Hyatt Regency) होटल के पास अपने कर्मचारियों की सैलरी देने के पैसे नहीं हैं और उसने अपना कामकाज अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। होटल ने एक बयान में कहा कि फंड की बहुत तंगी है, इसलिए अगले आदेश तक होटल बंद रहेगा। होटल का संचालन करने वाली कंपनी एशियन होटल्स (West) के पास से कोई फंड नहीं आ रहा, इसलिए कामकाज बंद करना पड़ा है। हयात रिजेंसी ने एक बयान में कहा, होटल के सभी ऑन-रोल स्टाफ को सूचित करना चाहते हैं कि हयात रिजेंसी मुंबई के ओनर एशियन होटल्स वेस्ट लिमिटेड से कोई फंड नहीं आ रहा जिससे कि कर्मचारियों की सैलरी दी जा सके या होटल का कामकाज चलाया जा सके। इसलिए तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लिया गया है कि सभी कामकाज अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएं। होटल अब अगले आदेश तक बंद रहेगा।

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार

गौरतलब है कि पिछले साल मार्च से ही कोराना की पहली लहर के बाद लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था के ठप पड़ने से टूरिज्म एवं ट्रैवल से जुड़े हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इस सेक्टर को सरकार से भी किसी भी तरह की खास राहत पैकेज भी नहीं मिल पाई है। कोरोना संकट के बीच लोगों ने सिर्फ जरूरी यात्राएं की हैं और अभी रेस्टोरेंट आदि का कामकाज शुरू ही होता, तब तक दूसरी लहर आ गई। महीनों तक होटल एवं रेस्टोरेंट बंद रहे, किसी तरह के गेस्ट नहीं आ रहे। ऐसे में कंपनियों के सामने बहुत बड़ा संकट है कि इनके स्टॉफ को सैलरी कब तक देते रहें। यही नहीं बिना किसी गेस्ट के भी इन होटलों के संचालन का डेली का भारी-भरकम खर्च होता है।

यूट्यूब ने एंड्रॉएड टीवी के लिए वीडियो प्लेबैक स्पीड कंट्रोल की शुरूआत की

सैन फ्रांसिस्को।

गूगल एंड्रॉएड टीवी के लिए यूट्यूब पर प्लेबैक स्पीड कंट्रोल (गति नियंत्रण) के लिए व्यापक रूप से सपोर्ट जारी कर रहा है।

प्लेबैक गति नियंत्रण के लिए अतिरिक्त सपोर्ट यूजर्स को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर वीडियो को धीमा या गति प्रदान करने की अनुमति देता है। 9टू5गूगल की रिपोर्ट के अनुसार, यह एक ऐसी सुविधा है जो लंबे समय से यूट्यूब वेबसाइट और मोबाइल ऐप में उपलब्ध है, लेकिन अब यह टीवी पर भी उपलब्ध है। यह विकल्प विस्तारित सेटिंग्स मेनू के अंतर्गत दिखाई देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बार जब आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके पास प्लेबैक गति को 0.25 गुणा गति से 0.5 गुणा, 1.25 गुणा, 1.5 गुणा और दोगुनी गति में समायोजित करने का विकल्प मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अन्य प्लेटफार्मों से 0.75 गुणा और 1.75 गुणा विकल्पों के साथ पेश किया गया है, लेकिन यह अभी भी सही दिशा में प्रगति कर रहा है। टीवी के लिए यूट्यूब पर प्लेबैक गति नियंत्रण हालांकि पूरी तरह से नया फीचर नहीं हैं और केवल अभी एंड्रॉएड टीवी/गूगल टीवी पोर्ट पर पेश किया गया है। यह विकल्प इससे पहले एलजी, सैमसंग और अन्य टीवी प्लेटफॉर्म पर लगभग समान ऐप पर शुरू हुआ था। एंड्रॉएड टीवी के लिए यूट्यूब कुछ यूजर्स के लिए वीडियो प्लेयर में वीडियो विवरण और अन्य चैनल शॉर्टकट जोड़ने का भी परीक्षण कर रहा है। उस परिवर्तन के विपरीत, हालांकि प्लेबैक गति नियंत्रण इस बिंदु पर अधिकांश यूजर्स के लिए व्यापक रूप से रोल आउट किए गए प्रतीत होते हैं।

ईईएसएल ने ऊर्जा दक्षता उपायों के क्रियान्वयन को लेमन ट्री होटल्स से करार किया

नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) ने ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के उपायों के क्रियान्वयन के लिए लेमन ट्री होटल्स के साथ करार किया है। बिजली मंत्रालय के तहत ईईएसएल एक संयुक्त उद्यम है। एक बयान में कहा गया है कि ईईएसएल ने लेमन ट्री होटल्स के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) किया है। इसके तहत लेमन ट्री होटल्स की देश में चुनिंदा परिसंपत्तियों में ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों का क्रियान्वयन किया जाएगा।तीन साल के इस एमओयू के तहत दोनों कंपनियां ऊर्जा दक्षता में सुधार वाले क्षेत्रों की पहचान करेंगी। इसके अलावा ईईएसएल और उसकी अनुषंगी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लि. (सीईएसएल) तथा ईपीएसएल ट्राइजेनरेशन की विशेषज्ञता का लाभ इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग जैसे क्षेत्रों में उठाया जाएगां ईईएसएल के कार्यकारी वाइस चयरपर्सन सौरभ कुमार ने कहा, ''हमें उम्मीद है कि अपनी परियोजनाओं के जरिये हम जो सफलता हासिल करेंगे उससे कई और खिलाड़ियों को ऊर्जा दक्षता और संरक्षण की पहल के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।'' लेमन ट्री होटल्स के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पाटू केशवानी ने कहा कि ईईएसएल के साथ भागीदारी से हम इन उपायों के प्रभाव का विस्तार कर सकेंगे और अपने कॉर्बन उत्सर्जन को कम करने को और उपाय ढूंढ सकेंगे। इससे हम कॉर्बन तटस्थता के अपने लक्ष्य के पास पहुंच सकेंगे।

टाटा डिजिटल करेगी क्योरफिट में 550 करोड़ रुपए का निवेश, इन कंपनियों को मिलेगी टक्कर

मुंबई:

टाटा डिजिटल ने सोमवार को कहा कि वह फिटनेस पर केंद्रित क्योरफिट हेल्थकेयर में 7.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 550 करोड़ रुपए) का निवेश करेगी। हालांकि, कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस निवेश से वह कितनी हिस्सेदारी हासिल करेगी। टाटा डिजिटल द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि क्योरफिट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी मुकेश बंसल टाटा डिजिटल में अध्यक्ष के रूप में एक कार्यकारी की भूमिका में शामिल होंगे और साथ ही क्योरफिट में उनकी अग्रणी भूमिका बनी रहेगी। गौरतलब है कि टाटा डिजिटल अपने ई-कॉमर्स कारोबार का विस्तार करने के लिए अधिग्रहण पर जोर दे रहा है। कंपनी का मुकाबला फ्लिपकार्ट, अमेजन और रिलायंस रिटेल जैसे दिग्गजों के साथ है। टाटा डिजिटल ने बयान में कहा कि भारतीय फिटनेस और वेलनेस बाजार सालाना 20 फीसदी की दर से बढ़ रहा है और 2025 तक इसके 12 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है और क्योरफिट टाटा डिजिटल को सक्रिय स्वास्थ्य प्रबंधन क्षेत्र में विस्तार करने में मदद करेगा। बयान के मुताबिक टाटा संस की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी टाटा डिजिटल लिमिटेड ने क्योरफिट हेल्थकेयर में 7.5 करोड़ अमेरिकी डालर के निवेश के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर दस्तखत किए हैं। हालांकि, इसके लिए जरूरी मंजूरियां ली जानी हैं। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, ÷क्योरफिट की साझेदारी हमारी स्वास्थ्य पेशकश के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है, जहां तंदुरुस्ती तेजी से उपभोक्ताओं के जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही है।÷ बंसल ने कहा कि टाटा डिजिटल से जुड़ना उनके और उनकी टीम के लिए एक रोमांचक कदम है, और क्योरफिट के साथ उनके द्वारा बनाए गए मूल्य की पहचान भी है। बंसल ने कहा, ''टाटा डिजिटल का हिस्सा बनने से हम अपने ग्राहकों के लिए अपनी पेशकशों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने में सक्षम होंगे।''

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

Sports

फ्रेंच ओपन : सीधे सेटों में जीत दर्ज करके स्विएतेक क्वार्टर फाइनल में

पेरिस।

आठवीं सीड पोलैंड की इगा स्विएतेक ने यूक्रेन की मार्टा कोस्टीयूक को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराकर यहां जारी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। 20 साल की स्विएतेक ने सोमवार रात खेले गए प्रीक क्वार्टर फाइनल में अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए 18 साल की यूक्रेनी खिलाड़ी को मात दी। उन्होंने 92 मिनट में यह मुकाबला अपने नाम किया। क्वार्टर फाइनल में अब स्वितेएक का सामना मिस्र के मारिया सकारी से बुधवार को होगा। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली मिस्र की पहली महिला खिलाड़ी बनी सकारी ने एक अन्य मुकाबले में सोमवार को अमेरिका की सोफिया केनिन को 6-1, 6-3 से मात दी।

फ्रेंच ओपन

नडाल क्वार्टर फाइनल में, जोकोविच से सेमीफाइनल में हो सकती है भिड़ंत

पेरिस।

13 बार के फ्रेंच ओपन विजेता स्पेन के राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अपने अगले मैच में जीत की स्थिति में वह सेमीफाइनल में वर्ल्ड नम्बर-1 नोवाक जोकोविच से भिड़ सकते हैं।नडाल ने सोमवार को खेले गए प्री-क्वार्टर फाइनल मैच में इटली के 19 साल के जानिक सिनर को 7-5, 6-3, 6-0 से हराया। अगले दौर में चार बार के मौजूदा चैम्पियन नडाल का सामना 10वीं सीड अर्जेंटीना के डिएगो स्वार्टजमैन से होगा, जिन्होंने अपना बेहतरीन फार्म जारी रखते हुए जर्मनी के जान लेनार्ड स्ट्रफ को 7-6(9), 6-4, 7-5 से हराया।नडाल 15वीं बार रोलां गैरों के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अब उनका सामना सर्बियाई सुपरस्टार जोकोविच से हो सकता है, जो इटली के टीनएजर लोरेंजो मुसेती के खिलाफ हुए फाइव सेटर में जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। 18 बार के ग्रैंड स्लैम चैम्पियन जोकोविच ने तीन घंटे 27 मिनट तक चले मुकाबले में मुसेती को 6-7(7), 6-7(2), 6-1, 6-0, 4-0 से हराया। अब वह इटली के माटेओ बेरेट्टीनी से भिड़ेंगे, जिनको स्विस स्टार रोजर फेडरर से वॉकओवर मिला। फेडरर ने रविवार को स्वास्थ्य कारणों से टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था।

जिदानसेक सेमीफाइनल में, चौथी सीड साफिन चौथे दौर में बाहर

पेरिस:

गैर वरीयता प्राप्त स्लोवेनिया की खिलाड़ी तमारा ज़िदानसेक ने 33वीं सीड स्पेन की पौला बदौसा को मंगलवार को तीन सेटों के संघर्ष में 7-5, 4-6, 8-6 से हराकर वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लेम फ्रेंच ओपन के महिला सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया जबकि चौथी वरीयता प्राप्त अमेरिका की सोफिया केनिन चौथे दौर में सोमवार को हारकर बाहर हो गई। जिदानसेक ने बदौसा से यह मुकाबला दो घंटे 26 मिनट के संघर्ष में जीता और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। केनिन को 17 वीं सीड यूनान की मारिया सक्कारी ने बड़ी आसानी से लगातार सेटों में 6-1, 6-3 से पराजित किया। सक्कारी ने यह मुकाबला मात्र एक घंटे आठ मिनट में जीता और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गयीं। पिछली चैंपियन और इस बार आठवीं वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्वीयतेक यूक्रेन की मार्ता कॉस्ट्युक को एक घंटे 32 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3, 6-4 से हराकर अंतिम आठ में पहुंच गई। इस तरह इस साल आठ क्वार्टरफाइनलिस्ट में से छह पहली बार किसी ग्रैंड स्लेम के अंतिम आठ में पहुंची हैं। आधी शताब्दी से ज्यादा समय से चल रहे ओपन युग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इससे पहले 2001 और 1976 के फ्रेंच ओपन और 1969 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में पांच क्वार्टरफाइनलिस्ट पहली बार पहुंची थीं। इन खिलाड़ियों में से एकमात्र ग्रैंड स्लेम विजेता स्वीयतेक हैं जो 20 साल की हैं। स्वीयतेक का क्वार्टरफाइनल में यूनान की सक्कारी से मुकाबला होगा।

सुपरबेट क्लासिक शतरंज - कोंस्टइंटिन नें अनीश गिरि को हराकर किया उलटफेर

बुकारेस्ट , रोमानिया (निकलेश जैन) रोमानिया की राजधानी में सुपरबेट चैस क्लासिक सुपर ग्रांड मास्टर टूर्नामेंट के तीसरे दिन तीसरे राउंड मे एक बार फिर मेजबान देश के खिलाड़ियों नें अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया और रोमानिया के शीर्ष खिलाड़ी और विश्व रैंकिंग मे 87 वे स्थान पर काबिज लुपलेसकू कोंस्टइंटिन नें विश्व नंबर 4 खिताब के प्रबल दावेदार नीदरलैंड के अनीश गिरि को मात देते हुए बड़ा उलटफेर किया । काले मोहरो से खेल रहे अनीश नें इंग्लिश ओपनिंग मे लगभग बराबर चल रहे खेल मे कोंस्टइंटिन के राजा के ऊपर जोरदार आक्रमण करने की कोशिश की और इसी दौरान 31 वीं चाल मे अपने वजीर की गलत चाल से खुद उनके राजा की मात होने की स्थिति आ गयी और खेल 39 चाल मे अनीश की हार से खत्म हुआ । इस जीत से कोंस्टइंटिन अमेरिका के फबियानों करूआना के साथ 2 अंक बनाकर सयुंक्त बढ़त पर आ गए है । अन्य परिणामों मे रूस के अलेक्ज़ेंडर ग्रीसचुक नें यूएसए के वेसली सो से ,अजरबैजान के तैमूर रद्जाबोव नें फ्रांस के मकसीम लागरेव से , यूएसए के लेवोन अरोनियन नें यूएसए के फबियानों करूआना से तो अजरबैजान के ममेद्यारोव नें रोमानिया के डेक डेनियल से बाजी ड्रॉ खेली ।

मानसिक थकान से निपटने के लिए भारतीय क्रिकेटरों को तीन हफ्ते का ब्रेक मिलेगा

लंदन।

जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में लंबे समय तक रहने के कारण मानसिक थकान की आशंका को देखते हुए भारतीय टीम प्रबंधन ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के बाद अपने खिलाड़ियों को तीन हफ्ते का ब्रेक देने का फैसला किया है। भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के बीच 18 जून से साउथम्पटन के एजियास बाउल में डब्ल्यूटीसी फाइनल खेला जाना है। इस मुकाबले के बाद भारतीय खिलाड़ियों को लगभग तीन हफ्ते (20 दिन) का ब्रेक मिलेगा और वे 14 जुलाई को दोबारा एकत्रित होकर इंग्लैंड के खिालफ चार अगस्त से नॉटिंघम में शुरू होने वाली पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला की तैयारी करेंगे। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जैसा कि कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ने रवाना होने से पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा था, ब्रेक दिया जाएगा। डब्ल्यूटीसी फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बीच छह हफ्ते का अंतर है इसलिए हमें खिलाड़ियों की देखभाल के मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा। ब्रिटेन के अंदर ही उन्हें ब्रेक मिलेगा, वे छुट्टी मना सकते हैं, दोस्तों और परिवार से मिल सकते हैं। बेशक टीम के खिलाड़ियों को एक साथ समय बिताने का मौका भी मिल सकता है लेकिन खिलाड़ी यह चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं। सूत्र ने कहा कि उनमें से अधिकतर खिलाड़ी कई बार ब्रिटेन आए हैं और देश में उनके मित्र और साथी हैं। यह उचित रहेगा कि वे उनसे मिल सकें। कोहली ने भी दो जून को रवाना होने से पहले प्रेस कांफ्रेंस में पीटीआई के इस सवाल का जवाब दिया था कि क्या दो श्रृंखलाओं के बीच 42 दिन के अंतर से टीम की तैयारियां प्रभावित होंगी। भारतीय कप्तान ने इसे टीम के लिए स्वागत योग्य ब्रेक करार दिया था और मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी उनसे सहमति जताई थी।

संक्षिप्त समाचार

फ्रेंच ओपन : चौथी सीड सोफिया केनिन चौथे दौर में बाहर

पेरिस : चौथी वरीयता प्राप्त अमेरिका की सोफिया केनिन वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लेम फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में सोमवार को हारकर बाहर हो गईं। केनिन को 17 वीं सीड यूनान की मारिया सक्कारी ने बड़ी आसानी से लगातार सेटों में 6-1, 6-3 से पराजित किया। सक्कारी ने यह मुकाबला मात्र एक घंटे आठ मिनय में जीता और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। पिछली चैंपियन और इस बार आठवीं वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्वीयतेक यूक्रेन की मार्ता कॉस्ट्युक को एक घंटे 32 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3, 6-4 से हराकर अंतिम 8 में पहुंच गईं। इस तरह इस साल 8 क्वार्टरफाइनलिस्ट में से 6 पहली बार किसी ग्रैंड स्लेम के अंतिम 8 में पहुंची हैं। आधी शताब्दी से ज्यादा समय से चल रहे ओपन युग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इससे पहले 2001 और 1976 के फ्रेंच ओपन और 1969 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में 5 क्वार्टरफाइनलिस्ट पहली बार पहुंची थीं। इन खिलाड़ियों में से एकमात्र ग्रैंड स्लेम विजेता स्वीयतेक हैं जो 20 साल की हैं। स्वीयतेक का क्वार्टरफाइनल में यूनान की सक्कारी से मुकाबला होगा।

ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके दीपक पूनिया को लगी चोट, पोलैंड ओपन से हटे

नई दिल्ली ।

ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके भारतीय पहलवान दीपक पूनिया बाएं हाथ की चोट के बढ़ने से बचने के लिए मंगलवार को पोलैंड ओपन से हट गए। तोक्यो खेलों से पूर्व यह अंतिम रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता है और पूनिया को 86 किग्रा वर्ग में चुनौती पेश करनी थी लेकिन वह अमेरिका के जाहिद वेलेंसिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले से हट गए। पता चला है कि 2019 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता को वारसॉ के लिए रवाना होने से दो या तीन दिन पहले अभ्यास के दौरान चोट लगी थी। भारतीय टीम के एक सूत्र ने बताया कि वह नहीं चाहता था कि उसकी चोट बढ़े और उसने महासंघ को सूचित कर दिया था कि वहां पहुंचने के बाद ही वह प्रतिस्पर्धा पेश करने पर फैसला करेगा। आज सुबह अपने हाथ के आकलन के बाद उसने नहीं खेलने का फैसला किया। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने इसकी पुष्टि की है। डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर ने कहा कि हां, हमने उसे विकल्प दिया था। हम पहलवानों पर दबाव नहीं बनाना चाहते, ओलंपिक करीब हैं, इसलिए जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं है। पूनिया ट्रेनिंग शिविर के लिए पांच जुलाई तक टीम के साथ रहेंगे। शिविर का आयोजन पोलैंड के महासंघ ने किया है। डब्ल्यूएफआई तुर्की, रोमानिया और रूस के साथ भी बात करके भारत के ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले पहलवानों के लिए ट्रेनिंग शिविर के आयोजन का प्रयास कर रहा है। पूनिया के हटने से प्रतियोगिता में अब सिर्फ तीन भारतीय पहलवान बचे हैं। ओलंपिक खेलों में 57 किग्रा में क्वालीफाई करने वाले रवि दाहिया पोलैंड ओपन में 61 किग्रा वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। विनेश फोगाट (53 किग्रा) और अंशु मलिक (57 किग्रा) शुक्रवार को महिला स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे।

ओलिम्पिक में पदक से कम के बारे में नहीं सोच रहे : कृष्ण बी पाठक

बेंगलुरू : भारतीय हॉकी टीम को पदक का प्रबल दावेदार करार देते हुए गोलकीपर कृष्ण बी पाठक ने कहा कि टीम तोक्यो ओलिम्पिक खेलों में पदक से कम के बारे में नहीं सोच रही है। भारतीय टीम अभी बेंगलुरू स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) केंद्र में अभ्यास कर रही है। भारत ने 1980 के मास्को ओलंपिक खेलों के बाद पदक नहीं जीता है लेकिन पाठक को विश्वास है कि वर्तमान टीम इतिहास रच सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने शीर्ष टीमों के खिलाफ अच्छा खेल दिखाया। सभी खिलाड़ी अपने खेल को लेकर आश्वस्त हैं और भारत के लिए इतिहास रचने को प्रतिबद्ध हैं। हम पदक से कम के बारे में नहीं सोच रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस साल ओलिम्पिक में हम पदक जीत सकते हैं। पाठक ने कहा कि टीम 23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलिम्पिक खेलों के लिए कड़ा अभ्यास कर रही है और तरेह की चुनौती के लिए तैयार है। इस 24 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि ओलिम्पिक अब दूर नहीं है और इसलिए हम अभ्यास सत्र में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोच हमारे लिए कड़े अभ्यास सत्रों की व्यवस्था की है और हम इनका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक ग्रुप के तौर पर पिछले कुछ वर्षों से अच्छा खेल रहे हैं और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ओलिम्पिक में हम अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलें। यह हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी लेकिन हम टोक्यो में इस चुनौती के लिए तैयार हैं। पाठक ने इसके साथ ही ओलिम्पिक जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में गोलकीपर और रक्षापंक्ति के अन्य खिलाड़ियों के बीच तालमेल को महत्वपूर्ण करार दिया। राष्ट्रीय टीम की तरफ से 50 मैच खेलने वाले पाठक ने कहा कि मैदान पर एक ही गोलकीपर हो सकता है लेकिन वह अकेला नहीं होता है। मैं रक्षापंक्ति के खिलाड़ियों के साथ उनकी योजनाओं के बारे में बात करता हूं ताकि मैं उनसे तालमेल बिठा सकूं। उन्होंने कहा कि यदि मैं डिफेंडरों के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठा सकता हूं तो फिर हमारी रक्षापंक्ति निश्चित तौर पर मजबूत रहेगी और हम आसानी से कोई गोल नहीं गंवाएंगे।

हम एम्बाप्पे को कभी नहीं बेचेंगे : पीएसजी अध्यक्ष

पेरिस। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) के अध्यक्ष नासिर अल खलैफी ने कहा है कि वह अपने स्टार फॉरवर्ड कीलियन एम्बाप्पे को कभी नहीं बेचेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि एम्बाप्पे अगले सीजन तक क्लब में बने रहेंगे। 22 साल के एम्बाप्पे ने इस सीजन में पीएसजी के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 42 गोल किए हैं और उनका अनुबंध जून 2022 तक का है। एम्बाप्पे को लेकर ऐसी अटकलें चल रही थी कि वह ला लीगा क्लब रियल मैड्रिड से जुड़ सकते हैं। स्काई स्पोर्टस की रिपोर्ट के अनुसार, खलैफी ने फ्रांस के इंटरनेशनल फुटबालर एम्बाप्पे के भविष्य को लेकर जारी अटकलों के बीच संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एम्बाप्पे अगले सीजन तक क्लब में ही रहेंगे। अल खलैफी ने कहा, मैं आपको स्पष्ट बता सकता हूं कि एम्बाप्पे पेरिस में ही बने रहेंगे। हम उन्हें कभी नहीं बेचेंगे। हम उन्हें कभी फ्री ट्रांस्फर पर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, वह कहां जा सकते हैं? महत्वाकांक्षा के मामले में कौन सा क्लब आज पीएसजी से मुकाबला कर सकता है? मैं केवल इतना कह सकता हूं कि चीजें ठीक चल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि हम एक समझौते पर पहुंच सकते हैं (नए अनुबंध पर)। यह पेरिस है, यह उनका देश है। उनका एक मिशन है, न केवल फुटबॉल खेलना, बल्कि लीग 1 को बढ़ावा देना।

गेंद के स्विंग होने पर संघर्ष कर सकते हैं कोहली : टर्नर

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और कोच ग्लेन टर्नर ने कहा है कि साउथम्पटन में न्यूजीलैंड के साथ होने वाली आगामी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल में अगर पिच और परिस्थितियां तेज गेंदबाजों और स्विंग के पक्ष में रहती हैं, तो भारतीय कप्तान विराट कोहली को संघर्ष करना पड़ सकता है। टर्नर ने द टेलीग्राफ से कहा, मैं इस बारे में अटकलें नहीं लगाना चाहता कि परिस्थितियों को लेकर कोहली सतर्क हैं या नहीं। लेकिन अगर पिच और परिस्थितियां तेज गेंदबाजों और स्विंग के पक्ष में रहती हैं, तो उन्हें अन्य बल्लेबाजों की ही तरह संघर्ष करना पड़ सकता है। जैसा कि न्यूजीलैंड में हुआ था। उन्होंने कहा, एक बार फिर से मैदान पर परिस्थितियां अहम होने वाली हैं। मुझे लगता है कि यह कहना सही होगा कि घरेलू परिस्थितियां, जहां बल्लेबाज सीखते हैं, एक खिलाड़ी की तकनीक और कौशल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पूर्व कप्तान ने कहा, हालांकि, ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में भारत में पिचें सीम गेंदबाजी में मदद कर रही हैं, फिर भी उनकी तुलना न्यूजीलैंड की स्थितियों से नहीं की जा सकती है। जब भारत ने आखिरी बार न्यूजीलैंड का दौरा किया था, तब भी परिस्थितियां अहम रही थीं।

सुनील छेत्री ने मेस्सी को पीछे छोड़ा, टॉप 10 में पहुंचने से एक गोल दूर

दोहा ।

भारतीय फुटबॉल टीम के करिश्माई स्ट्राइकर सुनील छेत्री अर्जेंटीना के सुपर स्टार लियोनेल मेस्सी को पीछे छोड़कर सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। 36 साल के छेत्री ने सोमवार को फीफा विश्व कप 2022 और एएफसी एशियाई कप 2023 के संयुक्त क्वालीफाईंग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की तरफ से दोनों गोल किये। इस तरह से उनके कुल अंतरराष्ट्रीय गोल की संख्या 74 हो गई है। विश्व कप क्वालीफायर में भारत की पिछले छह वर्षों में पहली जीत के नायक छेत्री सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में केवल पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो (103) से पीछे हैं।छेत्री बार्सिलोना के स्टार मेस्सी से दो और यूएई के अली मबखौत से एक गोल आगे हैं। मबखौत 73 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं। मेस्सी ने पिछले गुरुवार को चिली के खिलाफ विश्व कप क्वालीफायर मैच में अपना 72वां अंतरराष्ट्रीय गोल किया था जबकि मबखौत ने मलेशिया के खिलाफ अपनी गोल संख्या में बढ़ोतरी की थी। छेत्री ने सोमवार को जासिम बिन हमाद स्टेडियम में 79वें मिनट में पहला गोल दागा और फिर इंजुरी टाइम में दूसरा गोल करके भारत की जीत सुनिश्चित की।भारतीय कप्तान सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सर्वकालिक सूची में शीर्ष 10 में पहुंचने से केवल एक गोल पीछे हैं। वह हंगरी के सैंडो कोकसिस, जापान के कुनिशिगे कमामोतो और कुवैत के बाशर अब्दुल्लाह से एक गोल पीछे हैं। इन तीनों ने समान 75 गोल किए हैं। टीम की जीत और छेत्री के रिकार्ड पर खुशी व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कप्तान की आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए प्रशंसा की। पटेल ने ट्वीट किया कि हमारे कप्तान सुनील छेत्री ने लियोनेल मेस्सी को पीछे छोड़कर 74 गोल के साथ सक्रिय खिलाड़ियों में सर्वाधिक गोल करने वालों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंचकर एक और उपलब्धि हासिल की। कप्तान को बहुत बहुत बधाई और भविष्य में इस तरह की अन्य उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं। इस जीत से भारत 7 मैचों में 6 अंक के साथ ग्रुप ई में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत का अगला मैच 15 जून को अफगानिस्तान से होगा।

ओड़िशा एफसी ने भारतीय डिफेंडर लालरूआथरा के साथ करार किया

भवनेश्वर। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की टीम ओड़िशा एफसी ने टूर्नामेंट के आठवें सीजन को देखते हुए भारतीय फुटबॉल टीम के डिफेंडर लालरूआथरा के साथ करार किया है। मिजोरम के फुटबॉलर लालरूआथरा ने पिछले सीजन तक केरला ब्लास्टर्स एफसी का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने ओड़िशा एफसी के साथ दो साल का करार किया है। लालरूआथरा ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरूआत आइजोल एफसी के साथ 2015 में की थी और वह आई लीग की विजेता टीम का हिस्सा रहे थे। इसके बाद उन्होंने 2017 में केरला ब्लास्टर्स के साथ करार किया। लालरूआथरा ने अंडर-23 स्तर और भारतीय सीनियर टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है। लालरूआथरा ने कहा, मैं क्लब का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्सुक हूं और अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं। मैं नए सिस्टम, कोच और स्टाफ नेतृत्व में खेलने के लिए रोमांचित हूं और अपने खेल में सुधार लाने के लिए नई चीजें सीखने को लेकर उत्साहित हूं। ओड़िशा एफसी के सीईओ रोहन शर्मा ने कहा, मुझे लालरूआथरा का डिफेंस बेहद पसंद है और मुझे लगता है कि उनके आने से हमारा डिफेंस और मजबूत होगा। वह राष्ट्रीय टीम के बेहतरीन डिफेंडर हैं।

एनडीए

सेना में अधिकारी बनने का अवसर

सेना में नौकरी करने का एक अलग ही क्रेज होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि देश सेवा करने का बेहतरीन अवसर मिलता है। अब सैलरी भी काफी दमदार हो गई है। यही कारण है है कि अधिकतर युवा इस नौकरी को पाने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करता है।

अगर आप भी सेना में नौकरी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कम उम्र में ऑफिसर का रुतबा भी मिले, तो आपके लिए एनडीए बेहतरीन करियर विकल्प है। सेना में नौकरी करने का एक अलग ही क्रेज है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको देश की सेवा करने का बेहतरीन अवसर मिलता है। अब सैलरी भी अच्छी हो गई है। यही कारण है कि अधिकतर युवा इस नौकरी को पाने के लिए एनडीए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं।

एनडीए की परीक्षा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से काफी अलग होता है। अन्य परीक्षाओं में जहां मानसिक मजबूती देखी जाती है, तो वहीं इस परीक्षा में शारीरिक और मानसिक दोनों की मजबूती आवश्यक है। यही कारण है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाले स्टूडेंट्स कम उम्र में ही सैन्य अधिकारी बन जाते हैं। अगर आप में भी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है और ऑफिसर बनकर देश की बेहतर सेवा करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन अवसर है। एनडीए की ताजा परीक्षा के लिए केवल वही अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र साढे सोलह से उन्नीस वर्ष के बीच हो। सेना के तीनों अंगों के लिए पूर्णतया स्वस्थ अभ्यर्थियों की लंबाई कम से कम 157.5 सेंटीमीटर (एयरफोर्स के लिए 162.3 सेंटीमीटर) और इसी अनुपात में वजन होना चाहिए।

इसके अलावा, एयरफोर्स एवं नेवी के लिए फिजिक्स व मैथमेटिक्स विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि, आर्मी विंग के लिए किसी भी स्ट्रीम से बारहवीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। जो युवा बारहवीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यद्यपि उन्हें एसएसबी इंटरव्यू के समय 12वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पेश करना होगा।

कुल 900 अंकों की परीक्षा

एनडीए परीक्षा में दो विषयों की कुल 900 अंकों की परीक्षा होती है-पहला, मैथमेटिक्स और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट। दोनों के ढाई-ढाई घंटे के पेपर होंगे। मैथमेटिक्स का पेपर 300 और जनरल एबिलिटी का पेपर 600 अंक का होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और गलत उत्तरों के लिए अंक काटे जाएंगे। इसकी तैयारी के लिए प्लानिंग बनानी होगी और उसी के अनुरूप तैयारी करनी होगी।

मानसिक मजबूती जरूरी

अन्य परीक्षाओं में जहां मानसिक मजबूती देखी जाती है, तो वहीं इस परीक्षा में शारीरिक और मानसिक दोनों की मजबूती आवश्यक है। यही कारण है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाले स्टूडेंट्स कम उम्र में ही सैन्य अधिकारी बन जाते हैं। अगर आपमें भी ऑफिसर्स जैसी क्वालिटी है और ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन अवसर है।

कठिन परीक्षा के लिए रहें तैयार

रिटेन टेस्ट क्लियर करने वाले अभ्यर्थियों को सेना के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी द्वारा इंटरव्यू और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कॉल किया जाता है। परीक्षा के इस चरण का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी की पर्सनैलिटी, उसकी बुद्धिमत्ता और सेना में एक ऑफिसर के रूप में उसकी ऑफिसर लाइक क्वालिटी (ओएलक्यू) को जांचना-परखना होता है। एसएसबी के सेंटर देश के कई शहरों में स्थित हैं और अभ्यर्थी को उसके निकटवर्ती सेंटर पर ही बुलाया जाता है। आमतौर पर एसएसबी इंटरव्यू पांच दिनों का होता है, लेकिन इसमें पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट ही होता है, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है।

स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल होने वाले अभ्यर्थियों को वापस भेज दिया जाता है। शेष को अगले चार दिन तक कई टेस्ट देने होते हैं। इस दौरान उनका ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू बोर्ड तथा ग्रुप टास्क ऑफिसर द्वारा अलग-अलग तरीके से आकलन किया जाता है और उनकी ओएलक्यू को जांचा-परखा जाता है। एनडीए परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों को नेशनल डिफेंस एकेडमी, खडगवासला, पुणे में तीन वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है।

खास बात यह है कि इस तीन वर्ष की ट्रेनिंग के दौरान वे अपनी स्ट्रीम के अनुसार ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी करते हैं। इसके लिए उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एवं कंप्यूटर साइंस विषयों के साथ बीएससी का या पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री आदि विषयों के साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए का विकल्प होता है। हालांकि ट्रेनिंग के पहले वर्ष में तीनों सेनाओं के लिए चयनित अभ्यर्थियों को एक ही कोर्स की पढ़ाई करनी होती है।

दूसरे साल में उनके द्वारा चुने गए विंग यानी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के आधार पर उनके कोर्स का सिलेबस बदल जाता है। एनडीए में तीन वर्ष की ट्रेनिंग के उपरान्त कैडेट्स को उनके द्वारा चुनी गई विंग की विशेष जानकारी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। इसके तहत आर्मी के लिए चयनित कैंडिडेट्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी (देहरादून), एयरफोर्स के कैंडिडेट्स को एयरफोर्स एकेडमी (हाकिमपेट) तथा नेवी के लिए चुने गए कैंडिडेट्स को नेवल एकेडमी (लोनावाला) भेजा जाता है।

ट्रेनिंग के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले कैडेट्स को अंतत- उनके द्वारा चुने गए सेना के किसी एक विंग में कमीशंड ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है।

जॉब के प्रति लगाव जरूरी

यह सच है कि अधिकांश लोगों को अपना काम पसंद नहीं होता। कुछ उसे अधूरे मन से करते हैं, कुछ उसे बर्दाश्त करते हैं, पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है, जिन्हें अपनी पसंद का काम मिला हो और वह उससे अपनी जीवनशैली को भी सपोर्ट कर रहे हों। तो इसका मतलब क्या यह है कि शेष सब कुंठाग्रस्त रहें और ऐसे काम की तलाश में जुटे रहें, जो उन्हें पसंद हो। नहीं, ऐसा नहीं है।

आपको अपने कार्य का आनंद लेना चाहिए। ऐसा आपके जीवन के लिए, कई मायनों में कारगर रहेगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको जॉब पसंद ही हो। जॉब और उसे अपने तरीके से अंजाम देने में फर्क होता है। यह जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक कार्य के कुछ ऐसे पक्ष होते हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होते। फिर भी उन्हें हंसते हुए पूरा करना पड़ता है।

उदाहरण के लिए सेल्स का काम ही लीजिए। बहुत कम लोगों में सेल्स कार्य की क्षमता होती है, परंतु ऐसे व्यक्तियों को भी इससे कभी-कभार जुडऩा पड़ता है। कई बार तो ऐसे लोगों पर सेल्स की नीति तय करने तक की जिम्मेदारी आ पड़ती है। तो चाहे आपका बॉस आपके कार्य को पसंद न करता हो, आपको कम वेतन मिलता हो, कंपनी आपकी दृष्टि में आदर्श न हो.. पर इन समस्याओं के बारे में आप केवल इतना सोचें कि आपकी क्षमताओं की असली परख आपकी अपनी श्रेष्ठतम क्षमताओं के अनुसार होनी चाहिए।

इसकी शुरुआत प्रत्येक दिन के अंत में अपने कार्य के प्रति खुद को शाबाशी देने से शुरू करें। इससे आपको कंपनी के अंदर या बाहर ऐसे कार्य को खोजने की भी प्रेरणा मिलेगी, जो आपको पसंद है। और आप पाएंगे कि अपनी जॉब के जो पक्ष आपको पसंद नहीं हैं, वह धीरे-धीरे लाभदायक साबित हो रहे हैं।

जीवन में आपके और क्या शौक हैं? क्या आपको पढने्-लिखने का शौक है? कुकिंग, स्पोर्ट्स, कारें या कपड़े पसंद हैं। क्या आपका कोई ऐसा दोस्त, प्रेमी या परिवार है, जो आपके जीवन की धुरी है? यदि ऐसा कुछ है तो आप बधाई के पात्र हैं। आपको जीवन का एक मतलब मिला है। लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें लापरवाही से न लें, विशेषकर जिन लोगों का आपके जीवन में सबसे अधिक महत्व है, उनके प्रति तो बिल्कुल लापरवाह न रहें। इसका मतलब यह नहीं कि जो कार्य आपको पसंद नहीं, उसके साथ ताउम्र चिपके रहें। यदि आपकी जॉब पसंद की नहीं है तो नए सोपान तलाशने शुरू कर दें। पर जरूरी है कि इसके लिए एक विधिवत योजना बनाएं। यह भी याद रखें कि एक ओर नौकरी तलाशते रहें और दूसरी ओर अपनी मौजूदा जॉब के कुछ रोचक पहलुओं को आत्मसात करते रहें। यही अनुभव आगे भी काम आएगा।

जुनून है तो बनें पायलट

एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी सभी तरह के जॉब में पायलट की नौकरी युवाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय है। यहां न केवल भरपूर पैसा है, बल्कि अनोखा रोमांच भी इस जॉब में है। जहां तक सैलॅरी की बात है, तो एक कॉमर्शियल पायलट की औसत सैलॅरी एक लाख से शुरू होकर साढ़े चार लाख प्रति माह तक हो सकती है। इन दिनों एविएशन इंडस्ट्री में विदेशी कंपनियों के आने से पायलट की डिमांड खूब है।

बढ़ती मांग

भारतीय एविएशन इंडस्ट्री इन दिनों तेजी से विकास कर रहा है। दरअसल, सरकार की ओपन स्काई पॉलिसी ने इस इंडस्ट्री को अनेक अंतरराष्ट्रीय खिलाडिय़ों से जुडने् का मौका दिया है। परिणाम यह है कि इस क्षेत्र में न केवल प्राइवेट एविएशन प्लेयर्स, बल्कि एयरक्राफ्ट की संख्या में भी काफी बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है। सच तो यह है कि आगामी आठ-दस सालों में छह हजार से ज्यादा पायलट की मांग बढ़ती रहने की संभावना है।

कैसे होगा आगाज?

यदि आप पायलट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस से अवगत होना होगा, जैसे-कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए एसपीएल यानी स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और पीपीएल यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस प्राप्त करना होता है, लेकिन इससे पहले यह जरूरी है कि आपने बारहवीं में साइंस (फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथ्स) पढ़ा हो और खुद को मेडिकली फिट भी पाते हों। यदि इस फील्ड में करियर का आगाज करने के लिए उम्र-सीमा की बात करें, तो महज 16 वर्ष में ही आप फ्लाइंग के योग्य हो सकते हैं और 65 वर्ष की अवस्था तक इस करियर का आनंद ले सकते हैं।

कैसे मिलेगी एसपीएल सर्टिफिकेट

एसपीएल सर्टिफिकेट पाने के लिए यह जरूरी है कि बारहवीं में साइंस हो और आपकी न्यूनतम उम्र हो 16 वर्ष। इसके बाद डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (डीजीसीए) में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन इससे पहले यह जरूरी है कि आपके मेडिकल सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ-साथ बैंक गारंटी भी हो। डीजीसीए में पंजीकरण कराने के बाद आपको एक मौखिक परीक्षा से भी गुजरना होगा, क्योंकि इस परीक्षा में पास होने के बाद ही कोई एसपीएल सर्टिफिकेट के योग्य हो सकता है।

पीपीएल प्राप्त करने के लिए ...

एसपीएल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद पीपीएल यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस की जरूरत होती है। इसे प्राप्त करने के बाद ही कैंडिडेट खुद उड़ान भरने के योग्य बन सकता है। आप पीपीएल लाइसेंस के योग्य हैं या नहीं, यह एक लिखित परीक्षा के पास करने के बाद ही तय होता है। इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए भी बारहवीं में साइंस विषय होना चाहिए, और न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 17 वर्ष। इसके साथ-साथ आर्म्ड फोर्सेज सेंट्रल मेडिकल एस्टाविल्समेंट यानी एएफसीएमई से आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना होगा।

क्या पढ़ाया जाता है

कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए दी जा रही ट्रेनिंग में कैंडिडेट्स निम्नलिखित विषयों की बारीकियों से अवगत होते हैं..

एयर रेगुलेशंस

एविएशन मेटिओरोलॉजी, एयर नेविगेशन

एयरक्रॉफ्ट इंजिन (टेक्निकल और स्पेसिफिक दोनों)

प्लानिंग ऐंड कम्युनिकेशन (रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन के रूप में) आदि।

कौन हैं योग्य कैंडिडेट?

इस फील्ड में आने के लिए यह जरूरी है कि आई-साइट बेहतरीन हो। हाथ और पैरों का तालमेल यानी मोटर स्किल्स कॉर्डिनेशन काफी अच्छा हो।

यहां हैं संभावनाएं

शुरुआती दौर में आप किसी छोटे स्तर के एयरक्राफ्ट में ट्रेनी पायलट के रूप में जॉब कर सकते हैं। वैसे, एक कॉमर्शियल पायलट के रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों में करियर का आगाज कर सकते हैं..

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में

ह्णप्राइवेट एयरलाइंस में जैसे-जेट एयरवेज, सहारा, एयर डक्कन, किंगफिशर आदि।

ह्णइंटरनेशनल एयरलाइंस में, जिनका संचालन इंडिया से किया जाता है, जैसे- एयर कनाडा, कंतास, लुफ्थांसा, यूनाइटेड एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज आदि।

ट्रेनिंग की फीस

एडमिशन या ट्रेनिंग की फीस अलग-अलग फ्लाइंग स्कूलों पर निर्भर करती है। अमूमन भारत में सीपीएल यानी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस (200 घंटे की फ्लाइंग) के लिए 22 से 25 लाख के बीच फीस होती है। इसमें बोर्डिंग, यूनिफॉर्म आदि की फीस भी शामिल है (हालांकि मल्टीपल इंजिन के उड़ान की फीस इसमें शामिल नहीं होती है)। वहीं अब्रॉड में ट्रेनिंग की फीस 16 से 22 लाख के बीच होती है। हालांकि यह अलग-अलग देशों पर ही निर्भर करती है कि वहां कितनी फीस की डिमांड की जा सकती है! हां, ट्रेनिंग की अवधि होती है 14-18 महीने की।

कौन हो सकते हैं सफल पायलट?

एक सफल पायलट बनने के लिए जरूरी है कि आप न केवल मानसिक, बल्कि शारीरिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ हों। याद रखें, बेस्ट पायलट आप तभी बन पाएंगे, जब आपमें फ्लाइंग के प्रति जुनून होगा। साथ ही, आंख, हाथ, पैर और ब्रेन के बीच बेहतर सामंजस्य बेहद जरूरी है।

गवर्नमेंट की पहल

गवर्नमेंट ने फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि डीजीसीए ट्रेनिंग स्टैंडर्ड के लिए नए मापदंड तैयार करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को और बेहतर ट्रेनिंग मिल सके।

फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए ट्रेंड इंस्ट्रक्टर की भी जरूरत

एविएशन तेजी से विकास कर रहे इंडस्ट्रीज में से एक है। आने वाले आठ से दस वर्षों में 6 हजार से अधिक पायलट की जरूरत होगी। हालांकि इसके लिए फ्लाइंग स्कूल में फ्लाइंग की क्वालिटी ट्रेनिंग (ग्राउंड और स्काई) के पर्याप्त इक्विपमेंट्स के साथ-साथ ग्राउंड और फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए ट्रेंड इंस्ट्रक्टर की भी जरूरत है।

प्रशिक्षण संस्थान

- एशियाटिक इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी, इंदौर
- ब्लू डायमंड एविएशन, पुणे
- एक्यूमेन स्कूल ऑफ पायलट ट्रेनिंग, दिल्ली
- इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एविएशन, आईएसए, नई दिल्ली
- इंडियन एविएशन एकेडमी, मुंबई

कॅरियर का चुनाव रुचि के अनुसार ही करें

आज करियर के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ब्यूटी, फैशन , तकनीकी कला, हैल्थ, डिजाइनिंग इत्यादि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें यंगस्टर्स को अपनी सामर्थ्य, क्षमता एवं योग्यता का अधिकाधिक प्रदर्शन करने का मौका मिलता है।

जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है अपने करियर का चुनाव करना। इसलिए करियर का चुनाव करते वक़्त संबंधित क्षेत्र को जानना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो हर व्यक्ति में कोई न कोई ख़ास विशेषता होती है, नहीं होती है तो उसे पहचानने की शक्ति। इस गुण को कोई यदि सकारात्मक रूप से ले तो उसके लिए करियर बनाना बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि अपने स्किल्स के हिसाब से पहले ही करियर तय कर लें, जिससे आगे चलकर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए कुछ सरल तरीक़े हैं, जिन्हें आप आजमा सकते हैं।

सकारात्मक रुख़- विचार हमेशा आशावादी रखने चाहिए, जिससे लोगों को प्रभावित करना आसान हो जाता है। काम करके तो हर व्यक्ति थक जाता है, पर ज़िंदादिली का अहसास काम के माहौल में उब नहीं फैलने देता। आजकल हर दफ्तर में काम का दबाव बहुत होता है, ऐसे में नियोक्ता अपने कर्मचारियों से उम्मीद करता है कि वे दफ्तर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर कंपनी में सद्भावना का माहौल बनाए रखें। चाहे काम कितना भी मुश्किल हो, टारगेट पूरा करना कितना भी कठिन क्यों न हो, पॉजिटिव एटीट्यूट रखने वाले लोग अपना और अपने टीम मेंबर का उत्साह बनाए रखते हैं और काम को हर हाल में पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्किल की ज़रूरत डेस्क-जॉब, जैसे अकाउंटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ट्रांसलेटर, एडिटिंग, सब एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग इत्यादि में ख़ास कर होती है। इसलिए माहौल को हल्का बनाने की क्षमता रखने वाले और सकारात्मक सोच रखने वाले औसत व्यक्ति भी इन क्षेत्रों को चुन सकते हैं।

संवाद- बेहतरीन भाषा और बोल-चाल आपके करियर को किन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, यह शायद आप सोच भी नहीं सकते। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं, जो वाकपटुता से अपने आस-पास के माहौल को अनुकूल बना लेते हैं। दरअसल किसी भी काम को करते या बोलते समय अपना पूरा ध्यान काम पर लगा पाने के साथ ही यह आंक लेना कि सामने वाला किस प्रकार रिएक्ट कर रहा है और किस प्रकार सामने वाले को आकर्षित किया जा सकता है, ऐसी ही योग्यता को बेहतरीन कम्यूनिकेशन स्किल्स कहते हैं। ऐसे स्किल की ज़रूरत आज कई क्षेत्रों में है, जैसे-मार्केटिंग, एंकरिंग, जॉकिइंग, टेलीकॉम, टूरिज़्म, लैंग्वेज़ , पीआर इत्यादि।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

पाकिस्तान में कोविड-19 के 1,383 नए मामले, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,35,013 हुई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,383 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,35,013 हो गयी है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में बताया। पाकिस्तान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय ने बताया कि देश में सोमवार को संक्रमण से 53 और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 21,376 हो गयी है।

मंत्रालय से जारी एक बयान के अनुसार, ''पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,383 नए मामले आये हैं जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,35,013 हो गयी है।'' मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान में करीब चार महीने बाद कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में गिरावट के कारण मंगलवार को संक्रमण दर घटकर तीन प्रतिशत के नीचे पहुंच गयी। मंत्रालय के अनुसार, देश में 8,67,447 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और वर्तमान में 46,190 मरीजों का उपचार चल रहा है।

पाकिस्तान में बड़ा रेल हादसा : मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हुई, 100 से ज्यादा जख्मी

कराची। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सोमवार को हुई ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 62 हो गई। विपक्षी दलों ने मांग की है कि देश में हुए भीषण ट्रेन हादसों में से एक इस हादसे की वजह का पता लगाने के लिए तुरंत जांच की जाए। उल्लेखनीय है कि सोमवार को कराची से सरगोधा जा रही 'मिल्लत एक्सप्रेस' पटरी से उतर गई थी और सामने वाली पटरियों पर गिर गई जिससे रावलपिंडी से कराची आ रही 'सर सैयद एक्सप्रेस' उससे टकरा गई। टक्कर के कारण मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पलट गईं। यह हादसा सिंध के घोटकी जिले के ढरकी शहर के निकट हुआ। एआरवाई न्यूज के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 62 लोगों की मौत हो गई तथा 100 अन्य घायल हो गए। जिया न्यूज ने सुक्कुर में रेलवे के संभागीय अधीक्षक तारीक लतीफ के हवाले से बताया कि राहत अभियान पूरा हो चुका है तथा पटरियों को भी साफ किया जा चुका है। इस हादसे में 17 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई थीं, उन्हें तथा इंजिन को पटरियों से हटा लिया गया है। उन्होंने कहा, ''हमें रेल सेवाओं को बहाल करने के आदेश मिले हैं।'' रेलवे मंत्री आजम स्वाति ने कहा कि सुक्कुर संभाग में रेल की पटरियां खस्ताहाल हैं। उन्होंने विस्तृत जांच के आदेश देते हुए कहा, ''हमें इस हादसे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाना होगा।''

कनाडा में सांप्रदायिक हिंसा, ट्रक चालक ने मुस्लिम परिवार को कुचला, चार की मौत

टोरंटो (कनाडा)। कनाडा में एक व्यक्ति ने अपने वाहन से जानबूझ कर एक मुस्लिम परिवार के पांच लोगों को टक्कर मार दी। घटना में परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गयी और एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने सोमवार को इस बारे में बताया। अधिकारियों ने बताया कि वाहन चालक ने परिवार को मुस्लिम होने के कारण उन्हें निशाना बनाया। घटना लंदन के ओंटारियो शहर में रविवार रात में हुई। प्रशासन ने बताया घटना के बाद मॉल के पास से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि वाहन ने एक मोड़ पर पीड़ितों को रौंद दिया। शहर के मेयर एड होल्डर ने कहा, ''यह मुस्लिमों के खिलाफ सामूहिक हत्या का मामला है। नस्ली नफरत के कारण आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया।'' मृतकों की पहचान सलमान अफजल (46), उनकी पत्नी मदीहा (44), उनकी बेटी युमना (15) और 74 वर्षीया दादी के तौर पर हुई। बुजुर्ग महिला का नाम नहीं बताया गया। अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चे का नाम फैयाज बताया गया है। घटना के शिकार लोगों के परिजन ने एक बयान जारी कर इस बारे में बताया और कहा कि लोगों को नस्ली नफरत और इस्लाम के खिलाफ घृणा को रोकने के लिए खड़ा होना चाहिए। बयान में कहा गया, ''जो लोग भी सलमान और उनके परिवार को जानते थे उन्हें पता था कि वे बहुत अच्छे मुस्लिम थे। परिवार के लोग अपने-अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनके बच्चे भी अपने स्कूल में पढ़ाई में अच्छा कर रहे थे।'' घटना के बाद पुलिस ने वारदात स्थल की घेराबंदी कर दी और अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस प्रमुख स्टीफन विलियम्स ने कहा, ''हमारा मानना है कि मुस्लिम होने के कारण परिवार को निशाना बनाया गया।

कनाडा में भी होगी भारत बायोटेक की कोवैक्सिन की सप्लाई, अमेरिकी कंपनी से किया करार

हैदराबाद। भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के लिए अमेरिकी भागीदार ओक्यूजेन इंक कनाडा में इस टीके के अधिकार के विस्तार को भारतीय दवा कंपनी को अग्रिम में 1.5 करोड़ डॉलर का भुगतान करेगी। ओक्यूजेन ने नियामकीय सूचना में कहा कि वह उत्तरी अमेरिकी देश में कोवैक्सिन को वाणिज्यिक रूप से पेश किए जाने के एक माह के अंदर भारत बायोटेक को एक करोड़ डॉलर का और भुगतान और करेगी।

भारत बायोटेक ने तीन जून को कहा था कि उसने ओक्यूजेन इंक के साथ अपने करार का विस्तार करने का फैसला किया है। इसके तहत टीके की खुराक का कनाडा में भी वाणिज्यिकरण किया जाएगा। भारतीय कंपनी और ओक्यूजेन के बीच अमेरिकी बाजार में कोवैक्सिन के सह-विकास, आपूर्ति और वाणिज्यिकरण के लिए पक्का करार हुआ था।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस आने का दिया निमंत्रण

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के अपने समकक्ष वोलोदिमिर जेलेन्स्की को जुलाई में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने बताया कि बाइडन ने सोमवार को फोन पर बातचीत के दौरान जेलेन्स्की को आमंत्रित किया। गौरतलब है कि जेलेन्स्की ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की योजना और रूस-से-जर्मनी तक की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को लेकर सार्वजनिक तौर पर चिंता व्यक्त की थी।

इस पाइपलाइन का काम लगभग लगभग पूरा हो चुका है और इससे रूस, यूक्रेन से होकर गुजर पाएगा। बाइडन ने अपनी यूरोप यात्रा से पहले जेलेन्स्की को फोन कर उन्हें आमंत्रित किया। यह यात्रा अगले सप्ताह जिनेवा में सम्पन्न होगी, जहां बाइडन रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में काफी तनाव बना हुआ है।जेलेन्स्की ने निमंत्रण मिलने के बाद ट्वीट किया, '' फोन पर बातचीत के दौरान जुलाई में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण देने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन आपका शुक्रिया। मैं इस यात्रा और अमेरिका तथा यूक्रेन के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने को उत्साहित हूं।''

सुलिवन ने कहा कि बाइडन और जेलेन्स्की को '' अमेरिका तथा

यूक्रेन के संबंधों से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला और राष्ट्रपति बाइडन ने राष्ट्रपति जेलेन्स्की को बताया कि संबंधों के विस्तार के साथ वह यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता तथा आकांक्षाओं के साथ मजबूती से खड़ें रहेंगे।''यूक्रेन ने संकेत दिया कि बाइडन प्रशासन ने कीव को 9,00,000 कोविड-19 रोधी टीके देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

म्यांमार की सैन्य सरकार सू ची के खिलाफ अगले सप्ताह शुरू करेगी अदालती कार्यवाही

नेपीता (म्यांमार)। (एजेंसी)।

म्यांमार की सैन्य सरकार अपदस्थ नेता आंग सान सू ची के खिलाफ अगले सप्ताह सोमवार को अदालत में अपना मामला पेश करेगी। सू ची के वकीलों ने इस बारे में बताया। सेना ने फरवरी में निर्वाचित सरकार का तख्तापलट कर सू ची को गिरफ्तार किया था। तख्तापलट के खिलाफ जनविरोध मजबूत बना रहा और हाल के महीने में इसने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। सू ची के समर्थकों का आरोप है कि उनकी नेता के खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित, उनकी नीतियों को गलत ठहराने के लिए और तख्तापलट को सही साबित करने के लिए हैं। सरकारी अभियोजकों को राजधानी नेपीता की अदालत में 28 जून तक अपना पक्ष रखना होगा। सू ची पर पांच आरोपों में सुनवाई हो रही है। इसके बाद सू ची की ओर से बचाव पक्ष की टीम को 26 जुलाई तक अपना पक्ष रखना होगा। हर सप्ताह सोमवार और मंगलवार को अदालत में सुनवाई होगी। सू ची और दो अन्य व्यक्तियों अपदस्थ राष्ट्रपति विन मिंट और नेपीता के पूर्व मेयर म्यो आंग के लिए सोमवार को प्रक्रियात्मक सुनवाई के बाद खिन माउंग जॉ ने पत्रकारों को इस बारे में बताया। सू ची तथा उनके विश्वस्त दोनों नेताओं पर ऐसी सूचनाएं फैलाने का आरोप है जिससे अशांति पैदा हो सकती थी। साथ ही सू ची पर 2020 में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 महामारी के लिए तय पाबंदियों का कथित तौर पर उल्लंघन कर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कानून तोड़ने का आरोप भी है।

नई इजरायली गठबंधन सरकार रविवार को शपथ लेगी

तेल अवीव (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पहली बार एक दशक के बाद सत्ता से बेदखल करने वाले आठ-तरफा गठबंधन सरकार के लिए कई दिनों तक चली बातचीत के बाद रविवार को नई इजरायल सरकार शपथ लेने के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, नेसेट के अध्यक्ष यारिव लेविन ने मंगलवार को शपथ समारोह की तारीख की घोषणा की। नए गठबंधन के सदस्य, जो शुरू में दूर-दराज राजनेता नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में पिछले सप्ताह उनकी साझेदारी पर सहमत हुए थे, उनके इस सप्ताह पहले ही शपथ लेने की उम्मीद की जा रही थी। गठबंधन के सदस्य कथित तौर पर बुधवार को समारोह के लिए जोर दे रहे थे। रविवार के सत्र में नए स्पीकर के लिए केसेट वोट भी देखा जाएगा।

नए गठबंधन के आठ सदस्यों के पास सबसे कम बहुमत हैः 120 नेसेट सीटों में से 61 पर।

इसके अतिरिक्त, सदस्य अलग तरह के राजनीतिक क्षेत्रों से आते हैं जो आम तौर पर एक दूसरे के साथ अलाईन नहीं होते हैं।

हालांकि, पार्टियां नेतन्याहू को नापसंद करने के लिए एकजुट हैं। क्या नई सरकार का गठन आगे बढ़ता है, कि यह 12 वर्षों में नेतन्याहू के बिना पहली इजरायली सरकार होगी।

हालांकि, नेतन्याहू अभी भी सत्ता पर काबिज होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं । यह देखने वाली बात होगी कि क्या वह गठबंधन के किसी भी सदस्य को अब भी हिला सकते हैं? ऐसे में नया राजनीतिक प्रयोग शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। नेतन्याहू ने नए गठबंधन को शताब्दी की धोखाधड़ी कहा है। लंबे समय तक प्रीमियर का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारियों ने बेनेट पर हमला किया, जिन्होंने पिछले नेतन्याहू मंत्रिमंडलों में सेवा की है। यह चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो सकता है।

रूस ने कनाडा के नौ अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध, अनिश्चित काल के लिए रहेगी पाबंदी

मास्को। (एजेंसी)।

रूस ने विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को कैद करने के मामले में आरोपी अपने अधिकारियों के खिलाफ कनाडा के प्रतिबंध के जवाब में सोमवार को कनाडा के नौ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा के न्याय मंत्री और अटॉर्नी जनरल डेविड लैमेट्टी, कनाडा के पुलिस आयुक्त ब्रेंडा लुकी और सुधार सेवा आयुक्त एनी केली समेत कई अधिकारियों पर अनिश्चित काल तक रूस में प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। कनाडा में अंतरसरकारीय मामलों के मंत्री डोमिनिक लेब्लैंक, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए नीति निदेशक मार्सी सुरकेस, राष्ट्रीय रक्षा विभाग के उपमंत्री जोडी थॉमस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा प्रतिबंधित अधिकारियों में कनाडा सशस्त्र बल के लेफ्टिनेंट जनरल माइक रूलेउ और सैन्य खुफिया कमान के प्रमुख रियर एडमिरल स्कॉट बिशप और पुलिस उपायुक्त ब्रायन बरनन के नाम भी शामिल हैं।नवलनी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे मुखर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं। उन्हें जर्मनी से लौटने पर जनवरी में गिरफ्तार कर लिया गया था जहां उन्होंने नर्व एजेंट जहर के उपचार के बाद इससे उबरने के लिए पांच महीने बिताये।

अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का काम हो रहा पूरा, अब अफगानिस्तान के लोगों की सुरक्षा कैसे की जाएगी?

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया का आधे से अधिक काम पूरा हो चुका है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया चार जुलाई तक पूरी की जा सकती है और इस साल गर्मियों के अंत तक साजो-सामान के साथ सभी अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया जाएगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका के शीर्ष कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेन्जी इस सप्ताह रक्षा मंत्री लॉयड आस्टिन को अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई से संबंधित सैन्य विकल्पों के बारे में जानकारी देंगे।

अधिकारियों के मुताबिक अफगानिस्तान में सुरक्षा से जुड़े अभियानों के लिए कितने अमेरिकी सैनिकों की जरुरत पड़ेगी, यह सुरक्षा से जुड़ी जरुरतों के मुताबिक तय किया जाएगा, यह संख्या करीब एक हजार तक भी हो सकती है। मैकेन्जी के विचारों से पता चलता है कि यह अनिश्चित है कि युद्ध की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान को कितना अमेरिकी समर्थन मिलेगा। सैनिकों की वापसी के बाद यह चिंता का एक विषय है कि अमेरिका सरकार के साथ काम करने वाले अफगानिस्तान के लोगों की सुरक्षा कैसे की जाएगी। इसके अलावा कट्टरपंथियों के बारे में खुफिया जानकारी मुहैया कराने वाला तंत्र भी प्रभावित होगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी राष्ट्रपति जो बाइडन की राजनीतिक साख से भी जुड़ी हुई है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में पैदा होने वाली संभावित अस्थिरता भी चिंता का विषय है। 11 सितंबर को विश्व व्यापार केन्द्र पर हुए आतंकवादी हमले के जवाब में 20 साल पहले अमेरिका की ओर से शुरू किए गए युद्ध की महत्ता को लेकर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जनरल मैकेन्जी रक्षा मंत्री आस्टिन को बताएंगे कि अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट अथवा अन्य आतंकवादी समूहों के संभावित पुनरुत्थान पर नजर रखने के लिए आवश्यक हवाई निगरानी में कितने ड्रोन विमानों की जरुरत होगी। पहचान गुप्त रखे जाने की शर्त पर कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों में अमेरिकी सैनिकों और विमानों की तैनाती से संबंधित कोई विकल्प मौजूद नहीं है।

रूस के विरोध के कारण किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान अथवा उज्बेकिस्तान जैसे देशों के साथ कोई भी समझौता करना मुश्किल होगा। गौरतलब है कि तालिबान ने मंगलवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि वह अमेरिकी सेना के साथ सहयोग करने वाले अफगानिस्तान के लोगों पर हमले नहीं करेगा। तालिबान ने ऐसे लोगों से देश नहीं छोड़ने और अपने घरों की ओर लौटने की भी अपील की है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की आधिकारिक प्रक्रिया एक मई से शुरू हुई थी, उस समय अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 2,500 से 3,500 के बीच थी। बाइडन ने सेना को 11 सितंबर तक का समय देते हुए कहा कि सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की जाएगी।

भारतीयों के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट करने वाले कंपनी अधिकारी को हुई तीन हफ्ते की जेल

सिंगापुर। सिंगापुर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को मंगलवार को तीन हफ्ते जेल की सजा सुनाई गई। इस अधिकारी ने पिछले वर्ष अप्रैल माह में नस्ली ट्वीट किए थे जिनमें उसने भारतीयों तथा कोविड-19 को लेकर भारतीय प्रवासियों की निंदा की थी। एक मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया। चैनल न्यूज एशिया की खबर के मुताबिक, जैनल अबिदीन शैफुल बहारी ने दो आरोपों को स्वीकार कर लिया है जिनमें सिंगापुर में भिन्न नस्ली समूहों के बीच सौहार्द्र को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि को अंजाम देना शामिल है। सजा देते वक्त ऐसे ही दो अन्य आरोपों पर भी विचार किया गया। अप्रैल 2020 में पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति ने ट्वीट करके कोविड-19 को लेकर भारतीय प्रवासियों की आलोचना की है। यह ट्विटर अकाउंट जैनल का था। जैनल के वकील ने दावा किया कि उनका मुवक्किल ''नस्लवादी'' नहीं है और मजाक करने के दौरान उसने सीमा पार कर दी। जैनल ने मार्च से अप्रैल 2020 के बीच आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। जिला न्यायाधीश एस. जेनिफर मैरी ने कहा कि नस्ल और धर्म संवेदनशील मुद्दे हैं और लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि लापरवाही से की गई टिप्पणियों से सामाजिक व्यवस्था भंग हो सकती है। उन्होंने कहा, ''और जब ऐसी टिप्पणियां इंटरनेट के माध्यम से की जाती हैं तो उनकी पहुंच बहुत अधिक होती है तथा इससे शांति और नस्ली सौहार्द्र को ऐसा नुकसान होने की आशंका रहती है जिसे सुधारा नहीं जा सकता।'' न्यायाधीश ने कहा कि लगातार चल रही वैश्विक महामारी के कारण नस्ली तनाव पहले ही बढ़ गया है और ऐसे में सख्त संदेश देने की जरूरत है। उन्होंने जैनल से कहा कि ट्वीट में जो इस्तेमाल की गई थी वह बहुत खराब थी।

नाखून कुछ बदले बदले से लगें तो हो जाइए चौकन्ने! कहीं कोविड के कारण तो नहीं

ब्रिटेन। (एजेंसी)।

कोविड-19 के मुख्य लक्षण बुखार, खांसी, थकान और स्वाद तथा गंध के एहसास में कमी हैं। त्वचा में भी कोविड-19 के लक्षण देखे गए हैं। लेकिन शरीर का एक और हिस्सा है जहां वायरस का प्रभाव पड़ता है और वह हैं आपके नाखून। कोविड-19 संक्रमण के बाद, कुछ रोगियों केनाखूनों का रंग फीका पड़ जाता है या कई सप्ताह बाद उनका आकार बदलने लगता है - इसे ''कोविड नाखून'' कहा जाता है। एक लक्षण नाखूनों के आधार पर लाल रंग की अर्ध-चंद्र की आकृति बनना है। ऐसा लगता है कि यह कोविड से जुड़ी नाखून की अन्य शिकायतों सेपहले ही मौजूद था, रोगियों ने कोविड संक्रमण का पता लगने के दो सप्ताह से भी कम समय में इसे देखा है। कई मामले सामने आए हैं - लेकिन बहुत ज्यादा नहीं।

नाखून पर इस तरह की लाल अर्ध-चंद्र आकृति आम तौर पर दुर्लभ होती हैं, और पहले नाखून के आधार के इतने करीब नहीं देखी गई हैं। इसलिए इस आकृति का इस तरह दिखना विशेष रूप सेकोविड-19 के संक्रमण का एक संकेत हो सकता है। नाखून पर यह अर्ध-चंद्र क्यों बनता है, इसका एक संभावित कारण वायरस से जुड़ी रक्त वाहिका में क्षति हो सकती है। या फिर यह वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण हो सकता है जिससे रक्त के छोटे थक्के जमते हैं और नाखून का रंग फीका हो सकता है। रोगी यदि लक्षणमुक्त है तो महत्वपूर्ण रूप से, इन निशानों के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है - हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वे कितने समय तक रहते हैं। रिपोर्ट किए गए मामलों में यह कुछ में एक सप्ताह तो कुछ में चार सप्ताह रहे। शारीरिक तनाव के लक्षण कुछ रोगियों ने अपने हाथों और पैरों की उंगलियों के नाखूनों के आधार में नए अलग तरह की रेखाएं भी देखीं जो अमूमन कोविड-19 संक्रमण के चार सप्ताह या उससे अधिक समय बाद दिखाई देती हैं। सामान्यतः ये रेखाएं तब होती हैं जब किसी तरह के शारीरिक तनाव, जैसे संक्रमण, कुपोषण या कीमोथेरेपी आदि के दुष्प्रभाव के कारण नाखून की बढ़वार में अस्थायी रुकावट होती है। अब यह कोविड-19 के कारण भी हो सकते हैं। नाखून औसतन हर महीने 2 मिमी से 5 मिमी के बीच बढ़ते हैं, शारीरिक तनाव होने के चार से पांच सप्ताह बाद ये रेखाएँ ध्यान देने योग्य हो जाती हैं - जैसे-जैसे नाखून बढ़ता है,इनका पता चलता है। इसलिए तनावपूर्ण घटना के समय का अनुमान यह देखकर लगाया जा सकता है कि यह रेखाएँ नाखून के आधार से कितनी दूर हैं। इन रेखाओं के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, क्योंकि समस्या का समाधान होने पर यह ठीक होने हैं। वर्तमान में, उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता और नाखूनों में होने वाले परिवर्तन के प्रकार या समय सीमा के बीच कोई संबंध नहीं है। अन्य असामान्य निष्कर्ष उपरोक्त तथ्य कोविड संक्रमण के कारण नाखून में होने वाले दो सामान्य परिवर्तन से जुड़े हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने कुछ अन्य असामान्य घटनाओं को भी दर्ज किया।

एक महिला रोगी के नाखून आधार से ढीले हो गए और अंततः उसके संक्रमण के तीन महीने बादगिर गए। इस घटना को ओनिकोमाडेसिस के रूप में जाना जाता है। इस रोगी को इन परिवर्तनों के लिए उपचार नहीं मिला फिर भी बीमारी के कारण गिरे नाखूनों के नीचे नये नाखूनों को बढ़ते देखा जा सकता था, यह दर्शाता है कि समस्या अपने आप हल होने लगी थी। एक और मरीज के जांच में संक्रमित पाए जाने के 112 दिनों के बाद उसके नाखूनों के ऊपर नारंगी रंग का निशान देखा गया। इसका कोई इलाज नहीं दिया गया और एक महीने के बाद भी यह निशान कम नहीं हुआ था। इसके पीछे अंतर्निहित कारण अज्ञात है। तीसरे मामले में, एक मरीज के नाखूनों पर सफेद रेखाएं दिखाई दीं। इन्हें मीस लाइन्स या ट्रांसवर्स ल्यूकोनीचिया के नाम से जाना जाता है। वे कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि के 45 दिन बाद दिखाई दीं।

ये नाखून बढ़ने के साथ ठीक हो जाती हैं और उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि इन तीनों स्थितियों में सभी में नाखूनों में होने वाले परिवर्तन को हम कोविड-19 के संक्रमण से जोड़कर देख तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रत्येक मामले में गिने चुने रोगी हैं, इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि वे बीमारी के कारण थे। यह पूरी तरह से संभव है कि तीनों का इस स्थिति से कोई संबंध न हो। दरअसल इस तरह के लक्षणों को कोविड-19 के लक्षणों से निश्चित रूप से जोड़ने की पुष्टि के लिएअभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। हमें इसके लिए कई और मामलों की आवश्यकता होगी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 वाले सभी रोगियों में ये नाखून की स्थिति नहीं होगी। और इनमें से कुछ असामान्यताओं का मतलब यह नहीं हो सकता है कि किसी को कोविड-19 हो गया है। बेहतर यह होगा कि हमें इन्हें पिछले संक्रमण के संभावित लक्षणों के रूप में मानना चाहिए - और निश्चित प्रमाण नहीं।

-वासिलियोस वासिलीऊ, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, निखिल अग्रवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया और सुबोधिनी सारा सेलवेंद्र, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया नॉर्विच

ऊन के बिल्डर ने इंदौर के व्यापारी से ठगे 80 लाख, व्यापारी के फ्लैट अन्य को बेच दिए

क्रांति समय दैनिक

सूरत,शहर के वराछा क्षेत्र में रहनेवाले बिल्डर ने जमीन मालिक के साथ मिलकर सचिन जीआईडीसी क्षेत्र के ऊन क्षेत्र में गोल्डन पार्क नामक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के इंदौर में रहनेवाले व्यापारी 12 फ्लैट खरीदे थे और उसके लिए 87.42 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन बाद में बिल्डर ने व्यापारी को केवल रु 7 लाख रुपए लौटा दिए और उसके फ्लैट किसी अन्य को बेच दिए। व्यापारी ने बिल्डर के खिलाफ सचिन जीआईडीसी पुलिस थाने में बिल्डर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के इंदौर में माणेकबाग रोड स्थित अशोका कॉलोनी में रहनेवाले 50 वर्षीय फैसल इब्राहिम सुपेडीवाला इंदौर के सियागंज के गणपति प्लाजा में मेंग्लोर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन नाम से ड्रायफ्रूट और किराना के व्यापार करते हैं। फैसल को वर्ष 2012 में जमीन-मकान की दलाली करनेवाले उनके दोस्त गुलाल उस्मान पोठियावाला ने फोन कर सूरत के ऊन में गोल्डन पार्क प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। सूरत के रांदेर क्षेत्र में रहनेवाले गुलाल ने फैसल को गोल्डन पार्क प्रोजेक्ट में एक फ्लैट की कीमत रु 10 लाख बताई थी। गुलाल की सलाह पर फैसल ने सूरत के वराछा क्षेत्र निवासी प्रफुल सवजी नावडिया और उधना मगदल्ला इलाके में रहनेवाले जितेश राजेन्द्र कदम के पास गोल्डन पार्क में 12 फ्लैट बुक करवाए थे और वर्ष 2012 से 2013 के दौरान फैसल ने रु 87.42 का भुगतान भी कर दिया था। 12 में से 7 फ्लैट की बिक्री के कागजात बना दिए। जबकि पांच फ्लैट बिक्री कागजात बाद में बनाने का वादा कर दिया। बाद में फैसल ने कई दफा कागजात बनाने की कही, परंतु बिल्डर वादे पे वादा करता रहा। इस फैसल को सूरत के गुलाल से पता चला कि बिल्डर ने 7 फ्लैट किसी अन्य व्यक्तिको बेच दिए हैं। खबर मिलते ही फैसल सूरत आ गए और जितेश कदम से मिलकर रुपए वापस लौटाने की मांग कर की। जितेश ने केवल 7 लाख रुपए लौटाए और अन्य रकम के बदले फ्लैट देने का वादा किया। हांलाकि बाद में जिसेश ने फैसल का फोन उठाना भी बंद कर दिया। फैसल ने जब प्रफुल नावडिया से बात की तो उसने कहा कि गोल्डन पार्क प्रोजेक्ट उसने जितेश को सौंप दिया है। ऐसा कहकर प्रफुल ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। फैसल को रु 8042000 मिले और न ही फ्लैट। आखिरकार फैसल ने सचिन जीआईडीसी पुलिस थाने में प्रफुल सवजी नावडिया और जितेश राजेन्द्र कदम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरूकी है।

सरकारी नौकरियों में धांधली

सरकारी नौकरियों की लालच देकर युवकों को ठगने वाला गिरोह पुलिस की गिरफ्त में

क्रांति समय दैनिक

गांधीनगर, गांधीनगर पुलिस ने सरकारी नौकरी की लालच देकर भोले-भाले युवकों को ठगने वाले गिरोह को दबोच लिया है। पकड़े पांच आरोपियों में एक युवती वह है जो सरकारी नौकरियों में धांधली को लेकर हुए आंदोलन की हिस्सा थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी आई कार्ड और स्टाम्प समेत रु 2 लाख का माल सामान जब्त की है। गांधीनगर इंफोसिटी पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी दक्षिण गुजरात के विभिन्न जिलों में सरकारी नौकरी के वांच्छुक युवकों से रुपए ऐंठते थे। ग्राम सेवक, तलाटी,

जूनियर क्लर्क, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर की नौकरी दिलाने का वादा कर आरोपी रु 10000 से रु 2500000 रुपए लेते थे। पुलिस ने आरोपियों से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अलग अलग पदों वाले आई कार्ड समेत रु 200000 का माल सामान जब्त किया है। आरोपी दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले के हैं। दक्षिण गुजरात के और इनका शिकार हुए युवक भी दक्षिण गुजरात के होने का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार गिरोह के पांच लोगों में से एक युवती वह भी है जो सरकारी नौकरियों में धांधली को लेकर हुए आंदोलन के दौरान उसका हिस्सा थी।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीयन की पहल करने वाला गुजरात पहला राज्य: मुख्यमंत्री

क्रांति समय दैनिक

अहमदाबाद, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीयन करने की पहल करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के ऐसे 82 फीसदी छोटे श्रमिकों के परिश्रम के योगदान से ही राष्ट्र और राज्य का विकास संभव है। मंगलवार को गांधीनगर में असंगठित क्षेत्र और भवन निर्माण श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीयन के लिए ई-निर्माण पोर्टल और मोबाइल एप का ई-लॉन्च करते हुए उन्होंने यह बात कही। इस मौके पर श्रम एवं रोजगार विभाग के मंत्री दिलीपकुमार ठाकोर भी उपस्थित थे। पोर्टल और एप के जरिए पंजीयन कराने का यह कार्य भी इन-हाउस गुजरात इंफो पेट्रो लिमिटेड (जीआईपीएल) के मार्फत किया गया है, जिसके लिए उन्होंने बधाई दी। मुख्यमंत्री ने राज्य की विकास यात्रा की नींव में मौजूद श्रमिकों विशेषकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए आधार से जुडी स्मार्ट कार्ड योजना- यू-विन (असंगठित श्रमिक पहचान संख्या) के अंतर्गत 10 लाख श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हें विभिन्न लाभ मुहैया कराने की मंशा

विजय रूपाणी ने श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीयन के लिए ने ई-निर्माण पोर्टल और एप लॉन्च किया

जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'श्रम एव जयते' का महिमा मंत्र दिया है, तब श्रमिकों के कल्याण और उनके परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सहित अन्य मामलों की चिंता करना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि गुजरात की विकास यात्रा में श्रमिक शांति, जीरो मैन डेज लॉस, तालाबंद या हड़ताल रहित गुजरात की जो छवि है, उसमें सभी श्रमिकों का अहम योगदान है। रूपाणी ने कहा कि ऐसे सभी श्रमिकों के कल्याण की फिक्र करते हुए संतुलन कायम रखने के भाव से श्रमिक वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए यू-विन कार्ड को आधार के साथ जोड़कर एक ही कार्ड से सभी योजनाओं का

सार-समाचार

गुजरात में इसी सप्ताह मॉन्सून दे सकता है दस्तक

अहमदाबाद, गुजरात में इस वर्ष निर्धारित समय से पहले मॉन्सून के आगमन की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। बंगाल की खाडी में लो प्रेशर के कारण अरब सागर पर से दक्षिण पश्चिम दिशा में हवा चलेगी, जिसकी वजह से गुजरातके कई जिलों में इसी सप्ताह मॉन्सून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 से 13 जून के दौरान राज्य में कई जगह भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल गुजरात में गर्मी के साथ नमी के कारण काफी उमस है। अगले दो दिनों के दौरान राज्य के कई इलाकों में छुटपुट बारिश हो सकती है। बता दें कि पहले मौसम विभाग ने गुजरात में 20 जून के आसपास मॉन्सून के आगमन की संभावना व्यक्तकी थी। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मॉन्सून की दस्तक हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद अब 11 से 13 जून के दौरान मॉन्सून गुजरात में दस्तक दे सकता है। इससे पहले राज्य में प्रि मॉन्सून एक्टिविटी शुरूहो गई है। राज्य के कई जिलों में बरसाती माहौल बना हुआ है।

स्टैच्यु ऑफ यूनिटी प्रवासियों के लिए खुला, ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू

अहमदाबाद, कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद गुजरात सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत राज्य के पर्यटन स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरदार पटेल की दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा स्टैच्यू यूनिटी भी बंद कर दिया था। राज्य मे दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद फिर पर्यटन स्थलों को खोलने की कवायद तेज हो गई है। मंगलवार से गुजरात का आकर्षण स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरूहो गई है। प्रवासियों के आने से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत सफारी पार्क लंबे समय बाद गुलजार हुआ है। पर्यटकों के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थानीय लोगों के व्यवसाय को गति मिलेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के खुलने की खबर के बाद होटल और टैंट सिटी की इंक्वायरी शुरूहो गई है।

बहुत जल्द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इलाका देश में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला क्षेत्र बन जाएगा।

यहां आनेवाले पर्यटकों को डीजल के बजाए इलेक्ट्रिक बस सेवा उपलब्ध होगी। ई वाहनों के मेंटेनन्स वर्कशोप और चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र को प्रदूषण मुक्तक्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा और यहां केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को चलने की अनुमति होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी थी।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

बिहार के बांका में मदरसा भवन में विस्फोट, ध्वस्त हुई पूरी बिल्डिंग

बांका। बिहार के बांका में मदरसे के पास विस्फोट की खबर है। इस विस्फोट की चपेट में आने के बाद मदरसा भवन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और जांच में जुटी है। धमाके के बाद आसपास अफरा-तफरी का माहौल हो गया। विस्फोट को लेकर विभिन्न तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि पुलिस कुछ भी कहने से इंकार कर रही है। जानकारी के मुताबिक घटना बांका के नवटोलिया थाना क्षेत्र के एक मदरसे की है। बिहार के बांका के नागर क्षेत्र में एक मदरसे में विस्फोट होने पर स्क्कअरविंद गुप्ता ने कहा कि सुबह 8 बजे सूचना मिली तो टीम पहुंची। छत और दरवाजा गिरा हुआ है। अभी यह नहीं कह सकते कि विस्फोट कैसे हुआ। जांच के बाद बता पाएंगे। प्रारंभिक सूचना थी कि गैस सिलेंडर फटा है। उसके बाद सूचना मिली कि बम ब्लास्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण मदरसा काम नहीं कर रहा था। हम एफएसएल टीम और बम दस्ते के मौके पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल किसी के घायल होने का कोई सबूत नहीं है।

नोएडा के बादलपुर में अवैध रूप से बालू खनन करने वाले छह गिरफ्तार

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा के बादलपुर इलाके में बालू का अवैध रूप से खनन करने के मामले में मंगलवार को छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बादलपुर थाना के प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि अवैध बालू खनन के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने राजतपुर गांव के पास से आज सुबह फुरकान, हरीश, अमित नागर, प्रदीप, ओमबीर तथा सुनील समेत कुल छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि इनके पास से पुलिस ने चार ट्रैक्टर ट्रॉली तथा एक जेसीबी मशीन बरामद की है। उनके अनुसार, पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि ये लोग कई दिनों से अवैध रूप से बालू का खनन कर रहे थे।

आगरा के अस्पताल में 22 मरीजों की मौत पर बोले राहुल, जिम्मेदार लोगों पर तत्काल हो कार्रवाई

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगरा के एक निजी अस्पताल में कुछ हफ्ते पहले ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल के दौरान एक साथ 22 मरीजों की मौत होने संबंधी खबर को लेकर मंगलवर को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस खतरनाक अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जिस खबर का हवाला दिया उसमें कथित वीडियो के आधार पर कहा गया है कि 26 अप्रैल को ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल के दौरान 22 मरीजों की मौत हो गई थी।

मानसून से पहले मुंबई में हुई बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उसके निकटवर्ती इलाकों में मंगलवार को सुबह बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इसे मानसून से पहले की बारिश बताया है। मुंबई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग (आरएमसी) ने बताया कि सुबह 11 बजे तक यहां मालवणी, बोरीवली और दहिसर जैसे इलाकों में 30 मिमी तक बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने महाराष्ट्र में शनिवार को दक्षिण-पश्चिम मानसून पहुंचने की पुष्टि कर दी थी, जब मानसून तटीय रत्नागिरी जिले में हरनाई बंदरगाह में पहुंचा था।

मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए फंसा कर 12 महिलाओं का किया यौन उत्पीड़न, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई। नवी मुंबई पुलिस ने कम से कम 12 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में 32 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। महेश उर्फ करण गुप्ता के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी को सोमवार को मुंबई के मलाड इलाके से गिरफ्तार किया गया था।पुलिस पिछले चार महीने से आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने 'उच्च शिक्षित महिलाओं' को लुभाने के लिए वैवाहिक वेबसाइटों पर कई फर्जी प्रोफाइल बनाए। ऐसी वेबसाइटों के माध्यम से महिलाओं से संपर्क करने के बाद, वह उनसे उनके फोन पर संपर्क करता और एक पब, रेस्तरां या मॉल में एक बैठक तय करता था। इसी तरह से वह महिलाओं को अपना शिकार बनाता गया। पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े के अनुसार, आरोपी इन बैठकों के दौरान महिलाओं का यौन शोषण करता था।

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण की शुरुआत दिसंबर में होगी, ट्रस्ट का ऐलान

अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण की शुरुआत दिसंबर में होगी और इस दौरान मंदिर का ढांचा खड़ा करने के लिए पत्थर लगाने का कार्य किया जाएगा। मंदिर के ट्रस्ट ने सोमवार को यह जानकारी दी। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक, नींव भरने का कार्य अक्टूबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और दिसंबर से निर्माण के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसमें भव्य मंदिर का ढांचा तैयार करने के लिए पत्थर लगाने का कार्य किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के न्यासी अनिल मिश्रा ने पीटीआई- से कहा, दिसंबर में मिर्जापुर के गुलाबी पत्थरों को लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा और गुलाबी पत्थरों के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है। राम जन्मभूमि में ही इन पत्थरों को काटने एवं तराशने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 400 फुट लंबाई एवं 300 फुट चौड़ाई वाली 50 फुट गहरी नींव में निर्माण सामग्री के 10 इंच मोटाई वाले मिश्रण की 50 परतें बिछायी जाएंगी।

मुत टीकाकरण को प्राथमिकता दे सरकार, जरूरत हो तो संसद से अतिरिक्त बजट की अनुमति लेः कांग्रेस

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

कांग्रेस ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण के लिए राज्यों को केंद्र की ओर से टीका मुफ्त उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा में 'पारदर्शिता की कमी' का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि सरकार को इस वक्त देश में रोजाना टीकों की 80 लाख खुराक दिए जाने को प्राथमिकता देनी चाहिए और निजी अस्पतालों में भी लोगों को मुफ्त टीका मिलना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्र पर 'हेडलाइन आधारित सरकार' होने का आरोप भी लगाया और यह आग्रह किया कि राज्यों को टीके के आवंटन का मापदंड तय किया जाए, 'कोविन' पंजीकरण की अनिवार्यता निजी अस्पतालों के लिए भी खत्म की जाए और अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ने पर संसद का सत्र बुलाकर अनुमति ली जाए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के टीकाकरण के लिए राज्यों को 21 जून से मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा और आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह ऐलान भी किया कि कुल टीके में 75 प्रतिशत की खरीद सरकार करेगी और 25 फीसदी अब भी निजी अस्पतालों को मिलेंगे, लेकिन वे प्रति खुराक 150 रुपये से ज्यादा सेवा शुल्क नहीं ले सकेंगे। रमेश ने संवाददाताओं से कहा, ''हमें खुशी है कि मनमोहन सिंह, कांग्रेस, विपक्षी दलों की मांग और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की। उनकी घोषणा की यह पृष्ठभूमि है, लेकिन प्रधानमंत्री कभी सही पृष्ठभूमि जनता को नहीं बताते। वह जानकारियों को तोड़-मरोड़ कर रखते हैं।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ''प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है उस पर 50 हजार करोड़ रुपये खर्च होगा। सरकार ने टीकाकरण के लिए 35 हजार करोड़ रुपये आवंटित है। सेंट्रल विस्टा पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। सरकार के पैसे की कमी नहीं है, प्राथमिकता की कमी है।' उन्होंने सरकार से आग्रह किया, 'इस वक्त सिर्फ टीकाकरण की प्राथमिकता देनी चाहिए।

संसद का सत्र बुलाइए, समितियों की बैठक बुलाइए। टीकाकरण के अतिरिक्त बजट की अनुमति लीजिए।' उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री ने मुफ्त टीकाकरण और केंद्र की ओर से टीकों की खरीद की बात की, लेकिन यह भी कहा कि 25 प्रतिशत टीके निजी अस्पतालों को दिया जाएगा। यह नहीं बताया कि निजी अस्पतालों को किस मूल्य और किस आधार पर टीके दिए जाएंगे?'रमेश ने कहा, ''हमारी मांग है कि सरकारी और निजी अस्पतालों दोनों में टीकाकरण मुफ्त होना चाहिए। सभी भारतवासियों को मुफ्त टीकाकरण की सुविधा मिलनी चाहिए।'' उन्होंने दावा किया, ''निजी अस्पतालों को 25 प्रतिशत टीके देना खतरनाक है। यह देश और देशावासियों के हित में नहीं है।'' पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 'कोविन' पंजीकरण की अनिवार्यता को लेकर कहा, ''हमने कई बार कहा कि यह अनिवार्य नहीं होना चाहिए कि देश में बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। सरकार ने मांग सुनी, लेकिन पूरा नहीं सुनी। अभी सरकारी अस्पतालों में पंजीकण अनिवार्य नहीं है, लेकिन निजी अस्पताल के लिए है। हम फिर से कहना चाहते हैं कि सभी जगह कोव-विन पंजीकरण अनिवार्य नहीं होना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्यों को टीका के आवंटन का मापदंड आज भी पता नहीं है। हम मांग करते हैं कि केंद्र और राज्य मिलकर ये मापदंड तय करें। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि आवंटन में पारदर्शिता हो और कोई भेदभाव नहीं हो।' रमेश ने कहा, 'सरकार के कई मंत्रियों ने कहा है कि दिसंबर तक 100 करोड़ भारतवासियों को टीकाकरण हो जाएगा। सरकार के आंकड़े के अनुसार, अप्रैल के महीने में हर दिन टीकों की 30 लाख खुराक दी गई थी। लेकिन मई में 16 लाख खुराक प्रतिदिन दी गई। सात जून को फिर से 30 लाख खुराक दी गई।'

देश में रिकवरी दर 94.3 प्रतिशत, सिर्फ 209 जिलों में 100 से अधिक नए मामले : स्वास्थ्य मंत्रालय

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोरोना संक्रमण के ताजा मामले को लेकर जानकारी दी। लव अग्रवाल ने कहा कि जहां 7 मई को देश में प्रतिदिन के हिसाब से 4,14,000 मामले दर्ज किए गए थे, वे अब 1 लाख से भी कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 86,498 मामले देश में दर्ज किए गए। यह 3 अप्रैल के बाद अब तक एक दिन के सबसे कम मामले हैं। उन्होंने कहा कि 4 मई को देश में 531 ऐसे जिले थे, जहां प्रतिदिन 100 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे, ऐसे जिले अब 209 रह गए हैं।

लव अग्रवाल ने आगे कहा कि 3 मई को देश में रिकवरी रेट 81.8त्र था, अब रिकवरी रेट 94.3त्र हो गया है। पिछले 24 घंटों में देश में 1,82,000 रिकवरी हुई हैं। हर राज्य में अब रिकवरी की संख्या प्रतिदिन दर्ज किए जा रहे मामलों की संख्या से ज्यादा है। पिछले एक सप्ताह में मामलों की संख्या में 33त्र की गिरावट और सक्रिय मामलों में 65त्र की कमी आई है। 5त्र से कम सकारात्मकता वाले 15 राज्य हैं। कोविड-19 के नए मामलों में काफी कमी आने का सिलसिला लगातार जारी है, सात मई के चरम के मुकाबले आंकड़ो में लगभग 79 प्रतिशत की कमी आई है।

तीसरी लहर की आशंका पर बोलते हुए एम्स निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने कहा कि वैश्विक या भारतीय किसी भी डेटा में बच्चों के अधिक प्रभावित होने का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। दूसरी लहर में भी जो बच्चे संक्रमित थे, उन्हें हल्की बीमारी या सह-रुग्णता थी। मुझे नही लगता कि हमें भविष्य में बच्चों में गंभीर संक्रमण होगा।

राजनाथ ने भारत में रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने के लिए स्वीडन की कंपनियों को किया आमंत्रित

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को सैन्य प्लेटफॉर्म तथा उपकरणों के विनिर्माण में निवेश के लिए एक आकर्षक स्थल के रूप में पेश करते हुए मंगलवार को स्वीडन की अग्रणी रक्षा उत्पादन कंपनियों को देश में विनिर्माण के केंद्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। भारत-स्वीडन रक्षा उद्योग सहयोग विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि सरकार ने अनेक सुधार किए हैं जो न केवल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से बल्कि वैश्विक मांगों को भी पूरा करने में रक्षा उद्योग के लिए मददगार साबित होंगे। रक्षा मंत्री ने यह जिक्र भी किया कि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में सरकार ने स्वचालित रूप से 74 फीसदी तथा सरकार के रास्ते 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दी है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी केंद्रित एफडीआई नीति के चलते भारतीय उद्योग प्रामाणिक एवं उपयुक्त सैन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में स्वीडन के उद्योगों के साथ सहयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विदेशी ओईएम (ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर) अपने दम पर संस्थान स्थापित कर सकते हैं, वे इस काम के लिए भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी कर सकते हैं तथा 'मेक इन इंडिया' पहल का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया, ''एसएएबी जैसी स्वीडन की कंपनियां पहले से भारत में मौजूद हैं और मुझे भरोसा है कि अन्य स्वीडिश कंपनियां भी पाएंगी कि रक्षा विनिर्माण के लिए भारत निवेश का प्रमुख स्थल है। स्वीडिश कंपनियों और भारत के रक्षा उद्योग के बीच सह-उत्पादन तथा सह-विकास की अनेक संभावनाएं हैं। भारतीय उद्योग स्वीडिश उद्योगों को संघटकों की आपूर्ति भी कर सकते हैं।''

रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान किफायती एवं उच्च गुणवत्ता के उत्पादन से संबंधित है और इसका मूल उद्देश्य है 'भारत में बनाएं' और 'दुनियाभर के लिए बनाएं'। उन्होंने कहा, ''इस अवसर पर मैं स्वीडिश कंपनियों को उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में समर्पित रक्षा गलियारों में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं जहां पर वे राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त लाभों का और उच्च दक्षता प्राप्त कार्यबल का फायदा उठा सकते हैं।

सरकार को उम्मीद, सामान्य कार्यक्रम के अनुसार ही होगा संसद का मानसून सत्र

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश की रफ्तार को कम कर दिया था। हालांकि, एक बार फिर से मामलों में कमी देखी जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब कामकाज एक बार फिर से शुरू हो सकता है। कोरोना संक्रमण के कारण ही संसद का बजट सत्र बीच में ही स्थगित करना पड़ा था। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सामान्य कार्यक्रम के अनुसार ही संसद का मानसून सत्र शुरू हो पाएगा? इसी को लेकर आज संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद पटेल से सवाल किया गया। प्रह्लाद पटेल ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि संसद का मानसून सत्र जुलाई में अपने सामान्य कार्यक्रम के अनुसार ही होगा।

जब से यह महामारी शुरू हुई है तब से संसद के तीन सत्रों की अवधि घटायी गयी है और पिछले साल तो शीतकालीन सत्र रद्द ही करना पड़ गया था। सूत्रों ने बताया कि इस साल मानसून सत्र के आयोजन के तौर तरीकों पर अभी चर्चा चल रही है। जोशी कहा, '' मैं आशान्वित हूं कि संसद सत्र जुलाई में शुरू होकर सामान्य कार्यक्रम के हिसाब से चलेगा। हम संसद चलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि जुलाई में सांसदों और संसद के कर्मचारियों का टीकाकरण कर लिया जाएगा।'' प्रशासन को जुलाई में यह सत्र आयोजित करने का पूरा विश्वास है क्योंकि ज्यादातर सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के ज्यादातर कर्मियों एवं अन्य संबंधित पक्षों को कोरोना वायरस टीके की कम से कम एक खुराक तक लग चुकी है। आपको बता दें कि भारत में 63 दिन बाद 24 घंटे में कोविड-19 के एक लाख से कम मामले सामने आए और नमूनों के संक्रमित आने की दैनिक दर भी गिरकर 4.62 प्रतिशत हो गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में 66 दिन बाद 24 घंटे में सबसे कम 86,498 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,89,96,473 हो गई है। इससे पहले दो अप्रैल को 24 घंटे में 81,466 नए मामले सामने आए थे।

कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करें विश्वविद्यालय : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। (एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के निर्देश देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को नर्सिंग, फार्मेसी, बायो केमिस्ट्री तथा बायो टेक्नोलॉजी के नवीन पाठ्यक्रम तैयार करने चाहिए ताकि भविष्य में कोरोना जैसी महामारियों की चुनौती से निपटा जा सके। यहां जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के मद्देनजर विश्वविद्यालयों द्वारा नर्सिंग, फार्मेसी, बायो केमिस्ट्री तथा बायो टेक्नोलॉजी के नवीन पाठ्यक्रम तैयार करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोरोना जैसी महामारियों की चुनौती से निपटा जा सके।

सोमवार को मुख्यमंत्री के समक्ष उनके सरकारी आवास पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नये राज्य विश्वविद्यालयों के संचालन, राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं उनकी स्थापना तथा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार किया जाए ताकि 'हमें प्रतिभावान जनशक्ति उपलब्ध हो सके और वर्तमान परिस्थितियों एवं भविष्य की चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में सभी विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार नये विषयों का भी समावेश किया जाना चाहिए।'

अखिलेश यादव के टीका लगाने वाले बयान पर भाजपा की चुटकी, कहा देर आए दुरूस्त आए

लखनऊ (एजेंसी)।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण रोधी टीका लगवाने के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे देर आए दुरूस्त आए बताया। दरअसल यादव ने सुबह ट्वीट किया, जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना वायरस रोधी टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा की कि टीके वह लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ़ थे पर 'भारत सरकार' के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे व टीके की कमी से जो लोग टीका नहीं लगवा सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं।

इस पर भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया संपर्क प्रमुख नवीन श्रीवास्तव ने ट्वीट किया,'' जनाक्रोश को देखते हुये भाजपा से भारत की हुई वैक्सीन लगवायेंगे, देर आए दुरूस्त आए। श्रीवास्तव ने अपने इस ट्वीट में सपा प्रमुख को भी टैग किया। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में जब कोरोना वायरस का टीका आया था, तब सपा अध्यक्ष

अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा था कि टीकाकरण अभियान कैसे चलाया जाएगा और गरीबों को मुफ्त में टीका कब मिलेगा।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्हें देश के चिकित्सकों पर भरोसा है लेकिन सरकार पर नहीं।उन्होंने कहा था कि एक साल बाद, जब सपा की सरकार सत्ता में आएगी, हम सभी के लिए मुफ्त टीका सुनिश्चित करेंगे। यादव ने यह कहते हुए विवाद भी खड़ा कर दिया था कि वह खुद भाजपा का टीका नहीं लगवाएंगे, हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि वह वैज्ञानिकों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, हमें अपने डॉक्टरों पर पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार पर नहीं... यह अच्छा है कि कोरोना वायरस का टीका आ गया है, लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं, उस पर विश्वास करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नहीं। सोमवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने कोरोना वायरस रोधी टीका लगवाया था तब भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया था। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया था, एक अच्छा संदेश, आशा करता हूं कि सपा के कार्यकर्ता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी पार्टी के संस्थापक से प्रेरणा लेंगे।

वहीं, सोमवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था, सपा संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव स्वदेशी टीका लगवाने के लिए आपका धन्यवाद। आपके द्वारा टीका लगवाना इस बात का प्रमाण है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा टीके को लेकर अफवाह फैलाई गयी थी। इसके लिए अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए।

अब स्पीड पोस्ट से कराएं अस्थि विसर्जन, वेबकास्ट के माध्यम से देख भी सकेंगे

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

कोरोना महामारी कौ दौर में हो रही मौत के परिजनों के लिए डाक विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। डाक विभाग और ओम दिव्य दर्शन (ओडीडी) की इस पहल से अब आप अपने परिजनों की अस्थी-विसर्जन स्पीड पोस्ट के जरिए वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और गया के पवित्र गंगा में भेज सकते हैं। यह सामाजिक-धार्मिक मंच श्राद्ध अनुष्ठानों से पूजा कराएगी।वाराणसी क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि, 'कई लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान अपने प्रियजनों को खो दिया, लेकिन अंतिम संस्कार ठीक से नहीं कर सके। अब अस्थियों को डाकघरों से स्पीड पोस्ट के माध्यम से इन स्थानों पर भेजा जा सकता है',। पवित्र गंगा में अस्थि विसर्जन की परंपरा है और लोग वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और गया में अस्थि विसर्जन और श्राद्ध कर्म कर मृत आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं।

कैसे करे स्पीड पोस्ट?

कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को ओम दिव्य दर्शन के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। ओडीडी पोर्टल पर अस्थि विसर्जन या श्राद्ध समारोह के लिए पंजीकृत होने के बाद, अस्थि का पैकेट डाकघर के माध्यम से वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और गया को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है। अस्थि पैकेट को ठीक से पैक किया जाना चाहिए और उस पर बड़े अक्षरों में 'ओम दिव्य दर्शन' लिखा होना चाहिए, ताकि इसे अलग किया जा सके। भेजने वाले को पैकेट पर अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि लिखना होगा। स्पीड पोस्ट शुल्क सेंडर द्वारा ही वहन किया जाएगा।

स्पीड पोस्ट की बुकिंग के बाद सेंडर को ओम दिव्य दर्शन संस्था के पोर्टल पर स्पीड पोस्ट बारकोड नंबर सहित बुकिंग की सारी डिटेल अपडेट करना होगा। पोस्ट ऑफिस पर पैकेट मिलने के बाद उसे ओम दिव्य दर्शन के पते पर पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद, ओम दिव्य दर्शन संस्था, पैनल में शामिल पंडितों के माध्यम से, पूर्व-निर्धारित तिथि और समय स्लॉट पर श्राद्ध समारोह करेगी, जो मृतक के परिवार के सदस्यों को लाइव वेबकास्ट किया जाएगा। इसके बाद गंगा जल की एक बोतल ओडीडी द्वारा बुक की जाएगी और मृतक के परिवार के सदस्यों को संसद मार्ग डाकघर, नई दिल्ली से स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)